CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Decontrol of Sugar and its likely Repercussions on Price and Availability of Sugar in the Market

SHRI KALP NATH RAI (Uttar Pradesh) : Sir, I beg to call the attention of the Minister of Agriculture and Irrigation to the decontrol of sugar with effect from the 16th August, 1978, and its likely repercussions on price and availability of sugar in the market.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : Sir, sugar and sugarcane have been the subject matter of discussions in this august House on a number of occasions and we have had the opportunity of outlining the scope, objectives ana policy frame adopted by the Government on, these two important sectors. A detailed policy statement was made on the Floor of this House on Augu3t 10, 1978 setting out the essential ingredients of the new sugarcane and sugar policy. With all humility I would appeal to Shri Kalp Nath Rai and other Hon'ble Members not to inject politics in these sectors affecting crores of consumers, millions ot cane growers and lakhs of workers so vitally connected with sugarcane and sugar. The dual pricing policy in sugar was introduced in 196 7-68 and has been continually in operation for nearly a decade, except for a brief period of seven months in 1971-72. It had succeeded, to some extent, in stabilizing the cane area and increasing the sugar production as also in ensuring to the consumer a substantial portion of his direct requirement of sugar through the public distribution system. But, in recent years, with record increase in cane production, high level of stocks in the sugar economy, it became apparent that the dual pricing policy had outlived its utility.

This year we had an unprecedented sugarcane production—again a record—of 172 million tonnes and thanks to a series of measures taken by the Government, the off-take of cane by the industry amounted to 68 million tonnes, an increase of 19 million tonnes over the previous year. Both in absolute terms and in percentage of drawal of cane by the sugar industry which amounted to 39%, this is a record which would make a dispassionate observer proud of our record.

We were faced with an extraordinary situation of large cane availability, about 18 million tonnes more than the previous year. Our main objective was to maximize the off-take of cane. For this purpose we devised a number of measures, sucn as, reaucuon in excise auty on tree sale sugar, increase in the all India waited average levy price by about Rs. 18/- per quintal with effect from 1-3-1978, decision to export the full quota in effect of 6- 5 lakh tonnes of sugar during the current year, liberal credit facilities etc. The most important step was to give excise duty rebate for late season crushing and the current sugar season has been the longest in the last 30 years. A record sugar production of 65 lakh tonnes has also been achieved.

But in the process of increasing the sugar production, there have been certain attendant stresses and strains. The stocks as on August 7, 1978 were over 41 lakh tonnes, nearly double the level of stocks during the corresponding period last year. Internal sugar consumption had already been stimulated by about 22%—which again is a record for sugar and perhaps for any other commodity in a single year.—during the current sugar year. From December, 1977 onwards we had been allotting to the State Governments, for public distribution, a quantity of over 2-70 lakh tonnes as against the level of 2-05 lakh tonnes earlier by the previous Government. However, there were widespread allegations that a sizable portion of the levy sugar so released was coming back to the free sale market with adverse consequences on the excise revenue to the exchequer, depressing the free sale realization to the industry and therefore its ability to discharge its obligations to the cane growers, creation of black money in the economy etc. I wish to reiterate this Government's policy that while -we have the utmost concern for the consumers, we do not want to stick to rigid controls when they have lost their relevance and utility, as has happened in the sugar economy today. It is the Government's belief that larger production, high level of stocks and good prospects of cane and sugar for the next year would lead to benefit to the consumer only under the system of decontrol fostering competitive conditions in the industry. To ensure that reasonable and remunerative prices are paid to the sugarcane growers by the sugar industry, the statutory minimum cane price has been raised from the level of Rs. 8' 50 per quintal, at which it had been static for three years to Rs. 10 per quintal, linked to a recovery of 8- 5%.

I would like to assure that the Government are keeping a close watch on production, availability and prices of sugar. In the event of the prices going beyond levels considered reasonable by the Government we will not hesitate to take appropriate action in the interests of the consumers of sugar and the producers of sugarcane. I may assure the House that the points raised by the Hon'ble Members have been fully taken care of by the Government in a

[Shri Bhanu Pratap Singh]

manner-conducive to the growth of sugar-cane and- sugar economy of the country.

श्री कल्प नाथ राय : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो शुगरकेन के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दिया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं ।

सभापति महोदय, जनता सरकार में व सदन के सभी दल के लोगों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सवाल पर अपनी राय देश की जनता के हित में अवश्य व्यक्त करें । इस नीति के परिणामस्वरूप लगता है कि जनता सरकार नीतियों की मौत और सिद्धान्तों का कब्रिस्तान बन गई है ।

[Mr. Deputy Chairman, in the Chair]

उपसभापति महोदय, इस सरकार की दिशा क्या है ? इस सरकार का डाइ-रेक्शन कहां जा रहा है, इस सवाल के ऊपर विचार करना चाहिए । कपड़े के सवाल पर The Janata Government has surrendered before the tycoons and mill-owners.

जिस के परिणामस्वरूप जो हम ने वेल्फेयर स्टेट की कल्पना की थी, जो हम ने कहा था कि हम हिन्दुस्तान के गरीबों को सस्ता कपड़ा देंगे, इस वर्तमान सरकार की नीतियों से उन गरीबों को कपड़ा मंहगे दाम पर मिलेगा ।

उपसभापति महोदय, जनता सरकार ने छह महीने पहले सीमेंट का डिकंट्रोल किया और जिन तर्कों का उत्तर मंत्री महोदय ने यहां प्रस्तुत किया है उस के विपरीत आज सीमेंट बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बिहार, उत्तरप्रदेश में--मैं जनता पार्टी के मेम्बर पार्लियामेंट से पूछना चाहता हूं--आज 35 रु० और 40 रुपये बोरी भी अवेलेबुल नहीं है । उपसभापति महोदय, जो शुगरकेन के सम्बन्ध में इन्होंने एक पालिसी को बनाया उसका परिणाम आप देखिये । जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता का हस्तांतरण जनता पार्टी को किया 2 रु० 15 पैसे किलो चीनी का दाम था, कालान्तर में जनता सरकार ने उसे 2.30 पैसे कर दिया । कालानन्तर में चीनी का दाम 2.60 पैसे किया और इस डिकंट्रोल के पहले 2 रु० 75 पैसे चीनी का दाम किया। हमारी सरकार ने ड्यूअल प्राइस पालिसी रखी थी। हिन्दुस्तान के 6, 10, 20 करोड़ लोग जो गरीब हैं उन को सस्ते गल्ले की दुकानों से शुगर देने की जिम्मेदारी सरकार की थी और कुछ परसेंटेज शुगर चीनी मिल मालिक बाजार में बेचेंगे । यह पूरी की पूरी सरकार की दिशा पूंजीवाद की तरफ़ जा रही है । गरीबों की पीठ में छुरा भोंकना और लगा-तार पूंजीपतियों की मदद करना इस सर-कार का उद्देश्य हो गया है ।

आदरणीय उपसभापति महोदय, ब्लैक मनी का आपरेशन बन्द हो गया था लेकिन आज हिन्दुस्तान के करोड़पति, ब्लैक मार्केटियर सीमेंट का स्टाक कर के मार्केट में आर्टिफिशियल स्केयरसिटी पैदा कर दिए हैं जिस के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान के गांवों में रहने वालों को 40 रुपये की बोरी भी सीमेंट प्राप्त नहीं हो रहा है । एक तरफ यह सरकार गांवों की बात, किसानों की बात करती है । आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी किसान के बेटे हैं, वह गांवों के रहने वाले हैं, मैं उन से पूछना चाहता हू कि आपकी सरकार के सत्ता में आने के बाद जिन चीजों का उपभोग गांवों के गरीब लोग या शहरों के गरीब लोग या मजदूर लोग या मध्यम वर्गीय लोग करते हैं क्या उन चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं कि नहीं ?

उपसभापति महोदय, इस शुगर डि-कंट्रोल की पालीसी का परिणाम होगा कि हिन्दुस्तान के जो 15 करोड़ गरीब लोग

हैं, जो जीवन स्तर के नीचे जनता रहती है उसकी चीनी का दाम लगातार बढ़ता जाएगा । माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने कहा है कि इस नीति से यह नहीं होगा । जब सस्ते गल्ले की दुकानों से 2 रु० 15 पसे चीनी मिलती थी तो बाजार में चीनी का दाम साढ़े तीन रूपया था । जब आपने पूरी चीनी डिकंट्रोल कर दी तो उसका दाम और भी बढ़ेगा । उप-सभापति महोदय, मैं आजमगढ़ जिले से आया हूं, बलिया, गाजीपुर, होकर मैं आया हूं वहां पर चीनी का दाम 5 रुपये हो गया । मैं आप से पूछना चाहता हूं कि दो तीन महीने में या छः महीने बाद इस देश के बड़े बड़े मुनाफाखोर, बड़े बड़े स्टाकिस्ट इस पूरे देश की चीनी का स्टाक कर लेंगे । फिर ब्लैकमार्केटियरर्स की मदद से, स्टाकिटस, होर्डर्स की मदद से स्कैसिटी पैदा करेंगे बाजार में। जो सीमेंट का हाल हुआ वही शुगर का हाल होगा । आज बाजार में सीमेंट 40 रुपये बोरी भी नहीं मिल रही है जब कि पिछली सरकार के जमाने में 20 रूपये बोरी मिल रही थी और जितनी सीमेंट जिस को चाहिये उतनी मिल जाती थी । जो डि-कंट्रोल की नीति सरकार ने अपनाई है इस नीति के परिणामस्वरूप शुगर भी ब्लैक-मार्केटियर्स के हाथ में चली जाएगी। आज यह सरकार कपड़े के संबंध में अपनी नीति अलग रखती है, सीमेंट के संबंध में अलग नीति रखती है और शुगर के सम्बन्ध में अलग नीति। जो नीति शुगर के संबंध में अपनाई है इस नीति के परिणाम-स्वरूप हिन्दुस्तान के 40 करोड़ गरीब लोगों की पीठ पर छुरा मारा जाएगा और मुट्ठी भर पूंजीपति, मोनोपली हाउसेज की मदद करने की कोशिश की जाएगी।

यह तर्क दिया जाता है कि आज किसानों को फायदा हुआ है और किसी भी समाज-वादी देश में किसी भी वैलफेयर स्टेट के अंदर जब तक आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जिन्दगी की जरूरी चीजों की सप्लाई नहीं करेंगे उस कंटरी के अंदर कभी भी प्राइस सेट-अप नहीं कर सकते । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या पिछले 30 वर्षों में कभी भी गन्ना किसानों की, जो चीनी का उत्पादन करते हैं, इतनी दुर्गति हुई है और क्या अंग्रेजों की हुकूमत में भी कभी चार रूपये क्विंटल गन्ना बिका है । मैं आप से पूछना चाहता हूं कि खेती करने वालों की लगातार लागत खर्चा नहीं बढ़ता जा रहा है और सरकार की इस वर्तमान नीति के कारण आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ले कर सम्पूर्ण हिन्दुस्तान के किसानों की कमर इस गन्ना नीति के कारण टूट नहीं गई है ? एक तरफ गन्ना किसान जो गन्ना पैदा करता है उस से चार रूपये क्विंटल लेकर उसकी कमर तोड़ रहे हो और दूसरी तरफ डिकंट्रोल करके चीनी इतनी महंगी कर रहे हो। जब गन्ना का सीजन था तब उस से चार रूपये क्विंटल गन्ना लिया गया और अब जब गन्ना का सीजन खत्म हो गया, गन्ना खत्म हो गया तो चीनी बड़े-बड़े मिल मालिकों के हाथ में देकर डी-कंट्रोल कर दी है । इसका परिणाम यह होगा कि आज देश में जो करोड़ों रुपये के ब्लैक मार्किटियर्स हैं, हार्डर्स हैं, स्टाकिस्टस हैं सारी चीनी को खरीद कर स्टाक कर लेंगे और बाजार में चीनी मिलेगी नहीं । चीनी मिलेगी भी तो बहुत ऊंचे दाम पर मिलेगी और इस से देश की गरीब जनता की कमर टूट जाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चीजें पैदा करने वाले आज जितना मारे जा रहे हैं, गन्ना पैदा करने वाले किसानों की जितनी दुर्गति जनता सरकार में हो रही है उतनी कभी नहीं हुई। जो गन्ना किसानों के खेतों से पूंजीपतियों की मिलों में गया वह पांच रूपये क्विंटल पर गया । अब गन्ना नहीं रहा इसलिये डी-कंट्रोल कर दिया गया । इसका

[श्री कल्प नाथ राय]

शिकार कौन होगा ? इसका शिकार हिन्दुस्तान की गरीब जनता होगी, मध्यम वर्ग के लोग होंगे, मजदूर होंगे, रेलवे में काम करने वाले होंगे, --क्लर्क होंगे क्योंकि उनको दो तीन महीने बाद बाजार में चीनी नहीं मिलेगी। इस जनता सरकार से कहना चाहता हूं कि वह मुझे बताये कि दुनिया का कौन सा कंटरी है जहां जीवन की एसेंशियल कोमोडिटीज का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने भी एक पालिसी बनाई थी। यह कहा था कि मिलों को चीप कपड़ा तैयार करना होगा। उन्होंने कपड़ा तैयार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 6 रुपये, 8 रूपये, या 10 रूपये में खुले बाजार में बढ़िया साड़ी मिलती थी लेकिन आज यह सरकार, जनता सरकार कपड़ा-मिल-मालिकों को अपने आपको सरंडर कर चुकी है करोड़ों रुपये चंदा लेकर के। जनता सरकार ने जो नीति बनाई है उस के परिणाम-स्वरूप देश के गरीबी के स्तर से नीचे रहने वालों का आज जीवन दूभर हो गया है। जो सीमेंट के साथ हुआ है वही आज शुगर के साथ हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता सरकार को डर मध्यावधि चुनाव का है इसलिए जनता पार्टी के घटकों ने पैसा इकट्ठा करने के लिये आपस में कंपीटीशन चलाया हुआ है। कपड़ा मिल मालिकों से करोड़ों रूपये ले रहे हैं, सीमेंट मिल मालिकों से करोड़ों रूपये ले रहे हैं। इनको यह पता है कि जनता सरकार नहीं चलने वाली है और फरवरी-मार्च के महीने में चुनाव होने वाले हैं इसलिये इस सरकार ने चीनी मिल-मालिकों से करोड़ों रूपये लिये हैं और चीनी का डिकंट्रोल कर दिया है इससे देश की जनता की पीठ में छुरा मारा जा रहा है।

उपसभापति महोदय, हमारे देश की गरीब जनता को पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के द्वारा आवश्यक चीजें उपलब्ध कराने के अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है। आज हमारे देश में स्थिति यह हो गई है कि पूरी की पूरी सरकार की दिशा पूंजीवाद की तरफ हो गई है। पूंजीवाद की दिशा में यह सरकार कदम बढ़ाते जा रही है। इस देश का वर्तमान सरकार पर पूंजीपतियों और मल्टी-नैशनल्स का नियंत्रण हो गया है। गरीबों के हित के लिए जो कानून पिछली सरकार ने बनाये थे वे कानून भी खत्म होते जा रहे हैं।

दूसरा तर्क मंत्री महोदय ने यह दिया है कि चूंकि चीनी का उत्पादन ज्यादा हो गया, इसलिए हमको डिकन्ट्रोल करना पड़ा। मैं इन से पूछना चाहता हूं कि क्या पिछली सरकार के जमाने में चीनी का उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ था और क्या यह भी सही नहीं है कि चीनी का उत्पादन 37 लाख टन से बढ़कर 48 लाख टन नहीं हो गया था? पिछली सरकार की यह नियत थी कि इतनी चीनी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से गरीब लोगों को दी जाएगी और मिल मालिकों से उस के बदले में सब सीडी दी जाएगी। शेष चीनी मिल मालिक बाजार में खुले भाव पर बेच सकते हैं। इस प्रकार से पिछली सरकार ने डुअल प्राइस पालिसी अपना रखी थी। पिछली सरकार चाहती थी कि हिन्दुस्तान के गरीब लोगों को, छोटे कर्मचारियों को और सरकारी कर्मचारियों को 2 रु० 15 पैसे प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जाय। हिन्दुस्तान की 10 करोड़ गरीब जनता को 2 रु० 15 पैसे के हिसाब से चीनी दी गई। चीनी अब जिन्दगी की जरूरियातों में आवश्यक चीज हो गई है। एस० टी० सी० की हमारे पास रिपोर्ट है जिस में लिखा है --

S.T.C. delay has cost the country dear.

इस सरकार के विचारों के दिवालियेपन के

कारण ही हिन्दुस्तान की जनता को आज इन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है ।

श्री उपसभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

श्री कल्प नाथ राय : श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि मंत्री महोदय ने यह प्रश्न उठाया है कि पिछले सालों में चीनी का उत्पादन ज्यादा हो गया । सरकार पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के माध्यम से कीमतों को निर्धारित कर सकती है । यह सरकार की जिम्मेदारी है । सरकार इस जिम्मेदारी से पीछे हट नहीं सकती है । यह कहना कि चूंकि उत्पादन ज्यादा हो गया, इसलिए डिकंट्रोल करना पड़ा, यह कोई तर्क नहीं है । आप लोग चीनी का डि-कन्ट्रोल करके इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि डि-कंट्रोल करना किसी पूंजीवादी सरकार का ही काम हो सकता है । जब देश में स्कैयरसीटी होती है तो तब भी पूंजीवादी सरकार डिकंट्रोल करती है और जब उत्पादन ज्यादा होता है तो तब भी डिकंट्रोल किया जाता है । कोई भी समाजवादी सरकार और जनता का कल्याण चाहने वाली सरकार इस तरह की नीतियों पर नहीं चल सकती है । जनता का कल्याण चाहने वाली सरकार जिन्दगी की आवश्यक चीजों को अपने हाथ में रखती है और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जनता को कपड़ा, चीनी, सीमेन्ट, साबुन, और टूथपेस्ट आदि जरूरी चीजें देती है ।

श्री उपसभापति : आप कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री कल्प नाथ राय : इस साल इस सरकार ने 60 करोड़ रुपयों की मिल-मालिकों को सबसीडी दी है। पिछले 30 वर्षों में चीनी मिल-मालिकों को इतनी बड़ी एक्साइज

में रिलीफ नहीं दी गई है । लेकिन फिर भी यह जनता सरकार मिल-मालिकों के हाथ में खेल रही है । मेरा यह कहना है कि —

This Government is a prisoner in the hands of the sugar lobby. Th>'s Government which came into power was a prisoner in the hands cf the sugar lobby. This Government is destroying the interests of the common people in ever}-way. Until and unless this Government gees, the poor people of India cannot be protected.

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, माननीय सदस्य श्री कल्प नाथ राय जी को चीनी के बारे में अपनी बात कहनी थी, लेकिन वे बीच में सीमेंट और कपड़े इत्यादि को भी ले आए । मैं कपड़े और सीमेंट आदि का जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन चीनी के संबंध में निवेदन अवश्य करना चाहूंगा और केवल चीनी तक ही अपने को सीमित रखूंगा । दूसरा प्रश्न उन्होंने वाद का उठाया है और समाजवाद और पूंजीवाद की बात कही है । मैं इस बात को बार बार कह चुका हूं कि हम किसी वाद से बंधे हुए नहीं है । केवल इसलिए कि कुछ आपकी ऐसी विचारधारा कभी रही हो, इसलिए हम को उसी कदम पर चलना है, इसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं । हमारे सामने एक ही उद्देश्य है कि जनता को कैसे ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सकती है । आपने लेवी शुगर की बात कही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपके शासन काल में आपकी व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू थी तो क्या लेवी शुगर गरीबों के लिए उपलब्ध थी ? इस दिल्ली शहर के अन्दर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्या वे लेवी शुगर नहीं खाते थे और क्या ये लोग गरीबों की श्रेणी में आते हैं? आप गरीबों की आड़ में शहर के लोगों को क्या लेवी शुगर नहीं देते थे और दूसरी तरफ ग्रामीणों के लिए क्या व्यवस्था थी । आपके शासन काल की व्यवस्था जो थी वह मैं आपको

[श्री भानु प्रताप सिंह]

बताना चाहता हूं । सारी लेवी शुगर शहरों में बटती थी केवल बराए-नाम देहात में पहुंचती थी । व्यवस्था यह थी कि शहर में रहने वाले प्रति व्यक्ति को एक किलो दी जाए और गांव में पूरे परिवार को एक किलो दी जाए । यह आपका इन्साफ था ।

श्री इब्राहीम कलानिया (गुजरात) : यह गलत है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : यह रिकार्ड पर है । सब से पहले जनता पार्टी की हुकुमत ने गांव और शहर वालों को बराबर चीनी बांटने का फैसला किया । आपकी निगाह में गरीब केवल शहरों में रहते हैं। आपने कभी गांव वालों की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि उनको चीनी मिलती भी है या नहीं (*Interruptions*) श्रीमन्, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि लेवी शूगर शहरों में अमीरों को मिलती थी और देहात में गरीबों को नहीं मिलती थी । यह धारणा निराधार है कि लेवी शुगर केवल गरीबों के लिए थी । अब जो आपके राज्य में शुगर मिलती थी उसका जरा हिसाब-किताब में आपको बतलाना चाहता हूं । नवम्बर, 1977 में खुले बाजार में चीनी का भाव चार रुपये तीस पैसे था और लेवी शुगर का भाव दो रुपये पन्द्रह पैसे था । इसकी व्हेटेड एवरेज यानी जनता के ऊपर चीनी का भार जो था वह दो रुपये 90 पैसे था और जैसे कि मैं कह चुका हूं यह भार गरीबों पर भी था और अमीरों पर भी था। कम से कम आपके शासन काल डिस्टिंक्शन नहीं था । अब दो रुपये नब्बे पैसे के मुकाबले में जब नवम्बर, 1977 में आपकी नीति लागू थी उस समय यह व्हेटेड एवरेज उपभोक्ता को जो देनी पड़ती थी उसकी तुलना में मैं आपके सामने आज का समाचार पढ़ना चाहता हूं :

"Bombay: Sugar has, to the surprise of consumer, become quite cheap with the removal of price and distribution control on it. It is now retailed at Rs. 2-80 *per kg.* as aginst Rs. 4 a few weeks ago."

यह बम्बई का है। दिल्ली में यहां पर खारी बावली एक बाजार है उस में चीनी का भाव 21 तारीख की यानी कल दो रुपये अस्सी पैसे प्रति किलो था । . . .

श्री कल्पनाथ राय : यह शुगर लाबी का अखबार है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : यह अखबार नहीं है, वास्तविकता है । आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए । आपके जमाने में जो व्हेटेड एवरेज था उसे आज सारी शुगर सस्ते भाव पर बिक रही है । आपको यही बात खल रही है कि आपकी नीतियां निष्फल रही हैं वहां हमारी नीतियां यह नतीजा हासिल कर सकी हैं । आज देश में जो पिछले कुछ सालों में व्हेटेड एवरेज चीनी का दाम देना पड़ता था उससे कम पर चीनी मिल रही है । श्रीमन, इसके बावजूद मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि कहा गया यह भी भय है कि कोई होर्डिंग कर लेगा, रख लेगा, मुनाफाखोरी करेंगे । श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यापारी-वर्ग ज्यादा समझदारी रखता है । कल्प नाथ राय की बुद्धि से वे काम नहीं करेंगे यही बात उस समय भी कही गई थी जब चावल, धान और दूसरे अनाजों के आवगमन से प्रतिबंध हटाया गया था । बहुत शोर मचा था कि चावल मंहगा हो जाएगा, होर्डर चावल रख लेंगे, प्रोफिटेरिंग करेंगे । लेकिन क्या हुआ ? आज के दिन चावल पिछले साल से सस्ता है । सारे देश में . . .

श्री रोशन लाल (हिमाचल प्रदेश) : क्या रेट है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : सारे देश में पिछले वर्ष—एकाध मार्किट में— . . .

AN HON. MEMBER : No, no. this is a wrong statement.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: It is not wrong; I can give you the figures but on another occasion.

कहना चाहता हूं कि आज वह व्यापारी या उद्योगपति बहुत बड़ा मूर्ख होगा जो चीनी बचाकर रखेगा इस आशा में कि उसको उससे लाभ होगा । आपको मालूम नहीं है कि कितना बड़ा स्टाक है । जितना स्टाक था उससे दुगना है, आज हमारे पास इतना स्टाक चीनी का कारखानों में है कि अगले 11 महीने तक अगर एक दाना भी चीनी न बने तो इस देश के लोगों को चीनी की कमी नहीं पड़ सकती है, जबकि दो महीने के बाद चीनी मिलें फिर चालू होने वाली हैं और हमको आशा है कि अगल वर्ष भी चीनी की पैदावार वराये नाम चाहे कम हो जायें वरना कम होने वाली नहीं है । तो इतनी बड़ी होने वाली फसल में चीनी की पैदावार भी अधिकतम होगी, ऐसी स्थिति में आप समझते हैं कि कोई समझदार आदमी ऐसी आशा नहीं करेगा कि होर्डिंग और फाफिटीयरिंग होगी ।

आप सीमेंट की बात करते हैं । सीमेंट का उत्पादन देश की मांग से बहुत कम है इसलिए चीनी के उत्पादन से सीमेंट की तुलना करना केवल अपनी नासमझी का परिचय देना है । एक चीज तो इतनी अधिक है कि उसकी खपत की व्यवस्था करनी पड़ रही है, और दूसरी चीज इतनी कम है कि उसकी मांग नहीं पुरी हो पाती है । दोनों की तुलना कैसे हो सकती है । फिर मैं बार-बार अपने बयान में कह चुका हूं और फिर दोहराना चाहता हूं कि राज्य की जो ताकत है वह चली नहीं गयी है, अगर कोई भी, चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो अगर वह मुनाफाखोरी इत्यादि करेगा, और जो हमने संकेत कर दिया है कि इस प्राइस लेविल तक आना चाहिए था, अगर उससे ऊपर प्राइस जाती है तो फिर सरकार को इसमें एक मिनट का भी संकोच नहीं होगा कि चीनी का कन्ट्रोल करके उसी भाव पर चीनी जनता को दिलाये । हम कसी आइडियालाजी या वाद से बंधे हुए नहीं हैं । अगर हम समझेंगे कि इस बात की आवश्यकता है कि सारी चीनी को सरकार ले तो वह भी किया जायेगा लेकिन आज आवश्यकता इस बात कि है जो यह अधिक चीनी पदा हो गयी है उसकी खपत अधिक से अधिक बढ़ायी जाये और खपत बढ़ाने का एक ही तरीका है कि इसको मुक्त कर दिया जाये । हर जगह आसानी से मिल सके और ऐसे भाव पर मिल सके जो पहले के वेटेड एवरेज से कम हो ।

SHRI V. B. RAJU (Andhra Pradesh) : Sir, the Minister will kindly recall the statement made on 27th February in the Lok Sabha about the sugar policy. It says : "The House will recollect that at the beginning of the sugar season 1977-/8. Government had decided that the dual pricing policy for sugar should continue." This is the first part of the statement. Then it says : "The State Goveinments will be requested to ensure that the cane producers got at least the same price for cane as was being paid to them last year." Sir, the industry, the censumer, the producer of raw material tr day pre in the greatest difficulty because of the unstable policy that is pursued by the present Government unless the Government takes to medium-teim or Jrrg term measures. Sir this is a great counny and millions of people are involved. At that time, lhat is. on 27th February, just one day before the Budget was presented, the Government increased the consumer price by 15 paise. On that day, we had also mentioned about it. The consumer did not resist ; the consumer population, that is, the cemmen people who are in millions, did not res JM ; they did not protest also because they saw the reason that the cane producer should get something and, therefore, there was this increase in price.

I P. M.

Now on 10th August there is the de-control, What has happened during these four months of April, May. June and July, that has compelled the Government to decontrol ? What is the new-situation that has devricped to rhrrgc their policy ? The House was never apprised of >'t. There was no discussicn allowed. While the Parliament is sitting they announce decontrol. We would like to know the main objective rf decontrol categorically. Is it to protect the consumer, or to give a belter price to the cane grower, or to actually fill the pockets of the industrial magnates, or for the State to get more excise duty, or to see that the industrial worker in the factory gets better wages ? What is the objective ? Mr. Kalp Nath Rai

[Shri V. B. Raju]

hn rig'nly said about this. He is a young mm, emotional. The Minister shmld hiv; appreciated instead of criticising him. The point is, there was decontrol of cement when there was shortage and there is decontrol of sugar when there is surplus. What exactly does this control or decontrol mean in a big country like ours where it takes mialhs and years to pass a communication to the lowest level, it is not sufficient sitting in Delhi and passing an ord;r ? NDW, what is gJing to happen ? Tile miin reason for decontrol, as I understand, is the accumulation of stocks. It is not in the interest of the grower. I shall prove it. Will the Minister today assure the House that the cane grower will g:t at least what he was getting actually last year. H2 has only raised the minimum price from Rs. 8.5 to Rs. 10 psr quintal. In Andhra Pradesh where from I com?, the cost of cultivation is worked out to Rs. 159 per ton. That is, unless you pay Rs. 16 per quintal, it does not suffice. And the cane suppliers were actually sharing the profit. The cane growers were sharing a part of profit which the factories were making. What is it that you are assuring to the cane growers ? Tell me about that first.

I will com: to the consumer next. The motivation behind decontrol is to save the management of the factories from the problem of piled stocks and bank credit. The Minister has said, the prices have come down. Whose prices have come down ?

SHRI KALP NATH RAI : Gone up.

SHRI V. B. RAJU : No, no, let us accept that the prices have come down. The prices for rich consumers have come down. The rich consumers who were consuming more, and who were paying Rs. 3.80 and Rs. 4 per Kg. for them the prices have come down. And at whose expense ? At the expense of the common consumer. He used to pay Rs. 2.30 and now he has to pay Rs. 3.00. That is to say, you are actually sacrificing the interest of the poor consumer for the advantage of the rich consumer. Let us be very clear. It is not politics. You have appealed to Mr. Kalp Nath Rai not to mix politics with this. I am not mixing politics at all, I am only referring to your policy decision. You have taken a particular decision. We shall sec that it works well, but the question is that it is our responsibility and it is the responsibility of the House to warn the Government. Is it your policy to come to the rescue of the management and rich consumer or the poor consumer a nd the cane grower ? What is your defined policy ? The Minister says that the policy is aimed at more consumption. How can there be more consum-tion when the price for the poor consumer has actually been increased ? What is the hurdle in this country for industrial growth ? What is actually the defect of our economy ? Expansion has taken place in maunfacturing of certain luxury goods for which the market is very limited. The recession is in that sector because the number of rich consumers in the country is very small, is quite limited. Do you think that by decontrolling the consumption will go up ? I want to know how the consumption will go up. The consumption will not go up, because the common people have no purchasing capacity.

If you make it feasible for the poor people, if you reduce the prjee for the poor man, he will consume more. That is socialism. Therefore, I am afraid the consumption will not go up. I can tell the Minister that the consumption will not go up, but — I take the punt made by Mr. Kalp Nath Rai—scarcity will happen because you are giving an opportunity to black money which had been actually contained earlier. What had happened in the case of crmtnt? I refer to cement only to prove this fact. Cement had not suddenly become scarce; the black money cornered it. The technique in this country, the tricks of the trade are, create a scrace market, a psychology of scracjty and then squeeze the consumer.

I am summing up. I am sorry if I have taken a bit of time. I am afraid that this policy that is now being pursued is to destroy the public distribution system, I would have wished the Commerce Minister to be present here. Even yesterday when we were discussing on the Appropriation Bill, we referred to tlis matter. The Commerce Minister says-j "We will increase the number of ocm-modities for public distribution." But actually you have taken out sugar from the public distribution systom. The moment you decontrol it, it has gone out of that system. You are not bringing other commodities under public distribution. By shifting the. responsibility of producing cheap cloth from the mills to the hanolloom sector, the public distribution of cheap cloth to the const mer is no more there.

The dual pricing system is linked up with the public distribution system. Dual pricing is adopted with the deliberate intent of achieving two objectives. Sir, one is to see that the poor population of this country which has no purchasing power will get essential goods even below the economic price, «'. *e.* even below the

production cost, for which the rich must pay to compensate the losses of producers and manufacturers. This is the objective to see that more goods are available to the poor people. By doing away with diat policy the Government are denying that. The second objective is to transfer resources from the rich to die poor dirough die consumption pattern. These are the two objectives which for 30 years we have laboured to achieve and the present Government are destroying them. Therefore, we want an assurance from the Minister today : at what level the price to the poor consumer is going to remain ? Is it Rs 2-50 ? Are you assuring them that at Rs 2- 50 it will be available ? The Government has not committed anydiing in the statement. It merely says "at a reasonable price." Why do you keep it like diat ? As a matter of fact, why don't you say that it will [not increase Rs 2.80 for the consumer ? Why don't you say that ? You say 'minimum cane price'. While you say 'minimum cane price', you must assure the cane growers that if the factory management makes profits, die cane-growers will have a share in the profits and determine the percentage of share also.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : i_That is implied.

PTSHRI V. B. RAJU : That is not implied. You made a statement on the 27di of February. And you have made another statement on the 10th of August. How can we rely upon this unstable policy ? We are interested in the common consumer and the cane-growers. Can you assure us on these two points ? I want a catergorical assurance from you on these two points.

SHRI GHANSHYAMBHAI OZA : (Gujarat) : Is it true that sugar is selling at Rs. 6 a kilogram at Azamgarh, as mentioned by Mr Kalp Nath Rai ?

SHRI BHANU PRATAP SINGH : It is only his imagination.

SHRI KALP NATH RAI : I want to ask Shri Shahi. मैं चाहता हूं, नागेश्वर शाही जी इस बात को कहें, जो जनता पार्टी के मेम्बर पार्लियामेंट हैं। आज़मगढ़ से परसों आया हूं। 5 रू० किलो के भाव मऊनाथ भंजन और आज़मगढ़ सिटी में चीनी मिल रही हैं।

SHRI GHANSHYAMBHAI OZA : I accept your statement. I donot challenge it.

SHRI V. B. RAJU : This information is very serious. Sugar has become non-available in Kerala in the open market. This is the latest information from Kerala that sugar is not available in the open market. And the Kerala Government has addressed the Union Government that the agreed quota of sugar that was to have been made available to them earlier should be made available. Please assure the State Governments which are preserving public distribution system. They are keeping it up. they are not destroying it. Kerala is not destroying the public distribution system. So please supply them the agreed quota. Kerala has a well-knit public distribution system. Unless sugar is supplied to them at that price, the public distribution system will fail. It will have political implications.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : Sir, the hon'ble Member has raised many ~ questions. It becomes rather difficult when in the course of asking supplemen-taries a speech is delivered. But I will try to reply to the extent that I remember.

f First, of all, he has tried to make out that public distribution system implies dual pricing. Now, the public distribution system is not confined only to one commodity, that is, sugar. We are distributing many other commodities. Why do you not insist that in all other commodities there should be dual pricing, T and why do you come to the conduit sion. . . .

SHRI V. B. RAJU : Cereals.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : I did not interrupt when yon were speaking. Just to imply that because the dual pricing system has been given up, therefore, the public distribution system is being given up is without any basis. For many commodities we do not have this kind of dual pricing and yet the public distribution system tries to distribute those commodities. If we feel that there is some difficulty we will certainly make purchases direct from factories and supply them through the public distribution system.. . *((Interruption)* Let me first finish. You will get your chance. I will reply to your questions when your turn comes. Assurance has been sought regarding the sugar cane price. I have said that the suger price has been fixed at Rs 10 per quintal for 8.5 per cent recovery. Now from this it follows that for average 10 reccvery the price will be Rs • 11775 or Rs 11 -76. Even according to the cost of production that the hon'ble Member has mentioned, that is covered.

Secondly, he wants an assurance that if the factories make any profit on the basis of this, that profit would be shared. I give this assurance also to him that

[Shri Bhanu Pratap Singh]

if the factories make any profit that will be shared according to the Bhargava formula which is 50:50. That assurance is there.

Regarding the price of sugar he also wants some assurance. Under a free economy or under decontrol it is very strange that you ask for assurances. It is just not possible to indicate a figure simply because if next day the price rises even by paise or beyond they will come and say, 'Oh; you said it would be Rs 2.80 and now it is Rs 2-85 on an average.' Taking all die seasons and taking the country as a whole the price of sugar will not exceed Rs 2 75. But if somewhere it goes up to Rs 2 90 or even comes down to Rs. 2.70, then please do not say mat we had said that it would be Rs. 2.75 and, theretore, it would have to be only Rs 2-75- Under this kind of pricing mere will be slight variations from season to season and also from those parts of the country where sugar is manufactured or, say, somewhere in Jammu and Kashmir or in Tripura mere may be differences. But we are aware of that and we will take steps to ensure that even in far off places the sugar price does not go beyond a reasonable level. And I have already indicated the reasonable level, namely, not more than Rs 2-75.

I have given you me prices of Bombay and Delhi but I would also like to men-don mat the new system has come into force only on the 16th August, that is, only five days ago. The impact of that cannot be felt all over the country within five days. If there is some shortage anywhere it is because the trade was nervous. They did not know to what level it will go down. But rest assured mat the sugar prices will come down- I have indicated to you the level to which we expect mis price to come down. In fact, those have already come down.

And I may mention one fact more. This level of price is what we expect during me coming season when the sugarcane rice would be slightly reduced.

विपक्ष के नेता (श्री कमलापति त्रिपाठी) : श्रीमन् जब कल्प नाथ राय जी कह रहे हैं कि आजमगढ़ के टाउन में और वहां की कुछ और जगहों में 5 रूपये शुगर बिक रही है तो क्या इसकी कोई जांच करायेंगे ? क्या आपको इसका पता है कि इस कीमत पर वहां बिक रही है ?

एक बात मैं और पूछना चाहता था कि जब मीनिमम प्राइस शुगरकेन की 8 रुपये कुछ पसे थी तब किसानों को 11 और 12 रुपये क्विटल के दाम दिये गये, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमने 11 रुपये कर दिया। आपके 8 रुपये कुछ पैसे थे तो आपको पता होगा कि पश्चिमी व पूर्व उत्तर प्रदेश में तो 4, 5 रुपये क्विटल और 3 रु० क्विटल तक गन्ना बिक गया और अभी भी कितना गन्ना वहां खड़ा है जो शायद मेरा अपना अंदाज है कि वह पिरेगा नहीं, शायद जलाना पड़े। जब इतनी मीनिमम प्राइस थी तो गवर्नमेंट मौजूद थी और मीनिमम फिक्स प्राइस के नीचे इन्होंने गन्ना लिया तो सरकार ने कोई कार्यवाही की जिससे किसानों को पुरी कीमत मिल सके? भविष्य में जब आप मूल्य निर्धारित कर रहे हैं तो क्या ऐसे कदम उठा रहे हैं कि जितनी मीनिमम प्राइस फिक्स कर रहे हैं उतनी उनको मिले ?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, मैं आभारी हूं त्रिपाठी जी का कि उन्होंने ये प्रश्न पूछकर मुझे अवसर दिया है कि मै विस्तार पूर्वक इन बातों को समझाने की कोशिश करूं। पहला प्रश्न उनका यह है कि साड़े आठ रूपया जब दाम था . . .

श्री कमलापति त्रिपाठी : आजमगढ़ में जो कीमत है उसकी जांच करेंगे ? यह प्रश्न था।

श्री भानु प्रताप सिंह : आजमगढ़ की वात यह है कि मेरी जानकारी में तो है नहीं, लेकिन मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो, जब तक आप आजमगढ़ पहुंचियेगा, जब तक वहां की खबर लीजिएगा, तव तक चीनी वहां इतनी पहुंच चुकेगी कि सस्ती हो चुकी होगी। कोई आपस कहे तो आप उसे कहें कि यहां से 2.60 रु० के भाव पर ले जाए और मुनाफा कमाये। अगर तीन दिन के अन्दर वहां भाव न गिरे तो मैं चीनी वहां पहुंचा दंगा।

श्रीमन, प्रश्न यह उठाया है कि 8 रुपये का जब भाव था तो 12 और 13 रु० किसानों को क्यों मिलता था। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा डयवल प्राइसिंग सिस्टम मे ही सम्भव है। लेकिन मैं जब यह कहता हूं कि फैक्टरीज को मीनिमम प्राइस देना है तो मेरा मतलब बड़ी वक्यम पैन फैक्टरी से है। जो माननीय त्रिपाठी जी और कल्पनाथ राय जी कह रहे हैं वह गुड़ या खांडसारी यूनिट के लिए सस्ती हो सकती है जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं आपसे कहता हूं कि फैक्टरीज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फैक्टरीज में 5 रु०, 6 रु० और 4 रुपये क्विंटल तक गन्ना लिया है, उसका आपको पता होगा, खाली खांडसारी या गुड़ की बात नहीं है।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन, अगर यह सिद्ध हो जाए तो मैं इस सदन को आश्वासन देता हूं कि उस चीनी के कारखाने का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन आप इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास प्रमाण दें या किसी निष्पक्ष आदमी के पास आप इसको सिद्ध करें कि किसी भी बड़ी फैक्टरी ने साढ़े बारह या साढ़े 13 जो सरकार की तरफ से निश्चित थी उससे कम पैसा दिया है तो उस फैक्टरी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इसको सिद्ध करने के लिए आज भी आपके पास प्रमाण हो तो बताइये।

श्री कल्पनाथ राय : हजारों प्रमाण हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : आपका प्रमाण मैं मानता नहीं, त्रिपाठी जी भेजें तो मैं जरूर विचार करूंगा।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra) : Under the Act, he who produces sulphur-grade sugar should give the minimum price. How can he give five rupees ? He will go to jail if he gives five rupees.

श्री भानु प्रताप सिंह : त्रिपाठी जी, आपकी गलत सूचना है। आपसे मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रचार में न पड़ें। यह सर्वथा निराधार है। किसी भी चीनी के कारखाने ने, आर्गेनाइज्ड यूनिट के कारखाने ने, जो भाव निश्चित था उससे कम नहीं दिया है और अगर आप सिद्ध कर दें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस फैक्टरी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा।

श्री कल्प नाथ राय : मैं भानुप्रताप सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि वह खुद जाकर देख लें (*Interruptions*)।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : फैक्टरी का नाम लो।

श्री कल्पनाथ राय : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप नागेश्वर प्रसाद शाही के नेतृत्व मे एक टीम भेज दीजिए। अगर 6 रुपये क्विटल गन्ना नहीं बिका हो तो आप जो कहेंगे मै करने को तैयार हूं। आप अपनी पार्टी के आदमी को भेजिए। जनता पार्टी के मेम्बर्स का डेलिगेशन भेजिए।

श्री भानु प्रताप सिंह : कहां की बात आप कर रहे हैं। फैक्टरी का नाम लीजिए।

श्री कल्प नाथ राय : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है।

श्री भानु प्रताप सिंह : फैक्टरी का नाम तो लीजिए।

श्री कल्पनाथ राय : सभी फैक्टरियों में छः रूपयें क्विटल बिका है। आप पालियामेंट के जनता पार्टी के मेम्बरों की कमेटी भेज दीजिए।

श्री उपसभापति : ठीक है, अपनी बात कह ली।

श्री भानु प्रताप सिंह : आपकी जानकारी की कमी पर तरस आता है। श्रीमन मैं यह

[श्री भानु प्रताप सिंह]

समझाने की कोशिश कर रहा था कि साढ़े आठ के मुकाबले साढ़े 12, साढ़े 13 क्यों दी जा सकती थी, क्यों दी जा रही थी। इसके दो पार्ट हैं एक स्टेचुटरी मिनिमम प्राइस और दूसरा पार्ट है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं भार्गव फार्मूले के अनुसार प्रॉफिट शेयरिंग। जब डुएल प्राइस चलता है तो ज्यादा कीमत पर शुगर बाजार में बिकती है। अंत में जब यह हिसाब लगाया जाता है कि कारखाने साढ़े आठ रुपये की दर से ज्यादा मुनाफा कमाया तो गन्ने की कीमत और बढ़ जाती है। परन्तु उत्तर भारत की मिलों में ऐसा होता है कि वे अंतिम हिसाब लगाने तक प्रतीक्षा नहीं करते हैं। उत्तर भारत की मिलों में यह परम्परा है कि वहां की राज्य सरकारें अनुमान लगा लेती हैं कि खुले बाजार में यह भाव बिकेगा, बिकने वाला है और उसी के आधार पर वे फिर कहती हैं कि इतना आपको मुनाफा होगा इसलिये आप शेयरिंग करिये और इतनी कीमत अदा करिये। दक्षिण भारत की मिलों में ऐसा नहीं होता है। वहां पहले कम कीमत दी जाती है और फिर कारोबार खत्म हो जाता है, बिक्री हो जाती है तो मुनाफा लगाकर दुबारा डैफर्ड पेमेंट दी जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस आधार पर यह 13 रुपये कीमत दिलाई गई थी वह आधार ठीक सिद्ध नहीं हुआ। पिछले दो वर्षों से ऐसा हो रहा है कि जो आशा की गई थी कि खुले बाजार इतनी कीमत होगी उसमें कीमत गिरती चली गई। इसी के बाद जो सन् 76-77 में कीमत निश्चित की गई थी गन्ने की उसमें यह आधार बनाया गया था कि खुले बाजार में एक्साइज ड्यूटी छोड़ कर मिलों को 330 रुपये मिलेगा। लेकिन 330 रुपये उनको नहीं मिला। साल का जब हिसाब लगाया गया तो मालूम हुआ उनको 272 रुपये औसतन मिला। 1977-78 में जब साढ़े 12, साढ़े 13 रुपये निश्चित किये गये थे उस समय यह अनुमान लगाया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने और दूसरी सरकारों ने, कि खुले बाजार के भाव में एक्साइज ड्यूटी छोड़ कर 280 रुपये, चीनी मिलों को मिलेगा लेकिन उसके मुकाबले में उन्हें सिर्फ 255 रुपये मिला।

आज यह प्रश्न उठता है कि डीकंट्रोल क्यों किया गया। आप देखेंगे कि 280 के आधार पर कीमतें निश्चित की गई थीं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, ...

श्री भानु प्रताप सिंह : आपको बाद में मौका मिलेगा। सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा चाहे जितनी भी देर लगे।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं उस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मिलें दो रजिस्टर रखती हैं। एक सही रजिस्टर होता है और दूसरा गलत रजिस्टर होता है। आपको, सरकार जो आंकड़े वह देती हैं वह एक रजिस्टर से देती हैं और जो बेचती हैं वह दूसरे रजिस्टर से बेचती हैं। अगर उनको मिलता है चीनी का दाम 315 रुपये क्विंटल तो अपने रजिस्टर में 272 रुपये क्विंटल लिखते हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसका ध्यान जरूर रखें। मै यह प्राइवेट मिलों के बारे में कह रहा हूं। (*Interruptions*)

श्री भानु प्रताप सिंह : आपने अपनी बात कह ली अब मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि मैं हिसाब नहीं रखता हूं यह बात सही है, और मैं उन फैक्टरीज का भी हिसाब नहीं देखता हूं। लेकिन हमारे यहां एक ब्यूरो आफ कास्टस ऐंड प्राइसेज, सरकारी ब्यूरो बना हुआ है। उसकी कीमतों को हम मानते हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट मिलों के मुनाफे की बात है तो हम को धोखा दिया है और सरकार को भी धोखा दिया है। इन सारी बातों को आपने देख लिया है। हरियाणा में पांच फैक्ट्रियां हैं। उसमें से चार फैक्ट्रियां सहकारिता के आधार पर चल रही हैं। आज

के समाचार-पत्रों में आपने देखा होगा कि उन फक्ट्रियों ने हरियाणा की सरकार को कहा है कि यदि उनको तीन करोड़ रुपयों का अनुदान नहीं दिया जाएगा तो ये फैक्ट्रियां अगले वर्ष नहीं चलेंगी और एकदम से बन्द करनी पड़ेगी । केवल पूर्वाग्रहों के आधार पर नीतियां बनाना, मैं समझता हूं कि इस देश को गड्ढे में ले जाना है । कुछ तो हम पहले ही गलत ढंग से काम कर चुके हैं, इसलिए देश को उबारने के लिए कुछ नये ढंग से सोचना पड़ेगा ।

श्रीमन, मैं पहले यह कह रहा था कि जब हमने यह माना था कि 280 रु० मिलेंगे तो वह भी नहीं मिला । उनको सिर्फ 255 रु० मिले । अब हमारे सामने प्रश्न यह उठा कि यह जो घाटा हो रहा है इसको पूरा कैसे किया जाय क्योंकि यह कह देना तो आसान है कि कि आप केवल मिलों की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हम मिलों की तरफ इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि उनके साथ गन्ना उत्पादकों का भविष्य भी जड़ा हुआ है । अगर मिलें बन्द हो गईं तो करोड़ों किसानों की आमदनी का जरिया समाप्त हो जाएगा । आज यह समस्या हमारे देश के कुछ हिस्सों में खड़ी हो गई है । बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कुछ मिलें ऐसी हैं जो ओपन कम्पीटीशन में खड़ी नहीं हो सकती हैं । हमें इस बात की चिन्ता नहीं है कि मिलें बन्द हो जायगी बल्कि हमें चिन्ता इस बात की है कि अगर मिल बन्द हो गई, तो हजारों लाख मजदूरों और किसानों के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी । आज हमारे सामने समस्या यह है कि जो पुरानी मिलें हैं जो शायद कम्पीटीशन में बन्द हो जाय उनकी हम सहायता कैसे करें । इन मिलों के साथ हमारे देश के करोड़ों किसानों और मजदूरों का भविष्य जुड़ा हुआ है । इसलिए हम अगर मिलों की तरफ ध्यान देते हैं तो उसके पीछे यही भावना छिपी हुई है । मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं । जिस जिले से मैं आता हूं वहां पर एक शुगर फक्ट्री थी । वहां पर श्री कल्प नाथ राय और उनके साथियों ने इतनी हड़ताल करवाई कि वह मिलें बन्द हो गई । यह बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं । आज तक वहां के किसान रोते हैं और यह पूछते हैं कि यह मिल यहां से क्यों हट गई । इसलिए मैंने कहा कि मिलों के साथ गन्ना उत्पादकों का भविष्य निर्भर करता है और हमें यह जरूर देखना पड़ेगा कि वे अपना कारोबार ठीक प्रकार से कर सकें ।

मैं पहले ही यह निवेदन कर चुका हूं कि हमारे देश में जो मिलें प्राइवेट सेक्टर में हैं या पब्लिक सेक्टर में है या कोआपरेटिव सेक्टर में हैं, उन सब की दुर्दशा है । इसलिए हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम इस कमी को कसे पूरा करें । हमने एक्साइज ड्यूटी में कुछ कमी की तो शोर मचाया गया कि उनको कोई उपहार दिया जा रहा है । अगर यह राहत नहीं दी जाती तो अनेक मिलों के सामने कठिनाइयां पैदा हो जाती और हो सकता है कि कुछ मिलें बन्द हो जाती । अगर हम लेवी सुगर को 2 रु० 50 पैसे कर देते तो समस्या का कुछ समाधान हो सकता था ।

श्री कल्प नाथ राय : आपने मिल-मालिकों को सौ करोड़ रुपये की राहत दी है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : हमें अपने देश में विकास कार्यों के लिए भी धन की आवश्यकता है । हमने लेवी सुगर को 2 रु० 15 पैसे से बढ़ाकर 2 रु० 30 पैसे किया । अब अगर उसको 2 रु० 50 पैसे किया जाता तो 2 रु० 75 पैसे या 2 रु० 80 पैसे में से कौन-सा रास्ता बेहत्तर होता, इस पर विचार करना था । हमारा ऐसा विचार है कि इस नई प्रणाली से अवश्य ही कंज्यूमर को फायदा होगा और हमारे देश की समस्त जनता इससे फायदा उठाएगी क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी उसमें यह कहा जाता था कि गांवों में कंट्रोल की चीनी नहीं पहुंच

[श्री भानु प्रताप सिंह]

रही है। हमने राज्यों में प्रयास करके भी देख लिया, लेकिन फिर भी अनेक गांवों में कंट्रोल की चीनी नहीं पहुंच पाती थी। और उनकी संख्या उन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की संख्या आपके पूरे शहर क्षेत्रों से अधिक है। इस तरह आज जिनको साढ़े तीन रुपये, साढे चार रुपये तथा पांच रुपये जो आजमगढ़ में बता रहे हैं, आप धीरज रखिये दो दिन बाद पौने तीन रुपये और तीन रुपए के बीच में मिलेगी। यह ग्रामीण वर्ग है जो लाभांवित होगा। आपने देहात में शहरी लोगों में भेदभाव बरता है, यहां पर चार हजार रुपये जो तनख्वाह पाते हैं उन्हें लेवी शुगर मिलती है और गांव में जो तीन बीघे का किसान है उसको लेवी शुगर नहीं मिलती है, इसलिए यह आपका कहना कि लेवी शुगर हटा कर हमने गरीबों के साथ अन्याय किया है, ऐसी बात नहीं है। फिर सारे देश में मिठाई सस्ती हो गई है, मुझे आशा है कि चाय भी सस्ती होगी। यह सब चीजें कौन खरीदता है। क्या सब इसको अमीर ही खाते थे। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि सरकार ने जो निर्णय लिया वह ठीक लिया है। यह भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है कि जिस चीज की इतनी अधिकता हो और जिस चीज की खपत हम ढूंढते फिरें फिर उस चीज पर कंट्रोल क्यों रखें। उसको जितना कोई खरीदना चाहे, बेचना चाहे उस पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने सही दिशा में फसला लिया है। इसका लाभ देश के उन अधिकांश उपभोक्ताओं को होगा जो गांव में रहते हैं जिनको अभी तक चीनी नहीं मिल पाई थी और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस पर कोई हकतलफी किसानों की भी नहीं हुई है और न होगी। हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई लांग टर्म सूटेबल पालिसी होनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लांग टर्म पालिसी तभी संभव है जब कमांड इकोनोमी हो, जब सरकार को यह अधिकार हो कि वह क्षेत्रफल भी निश्चित करे, हर चीज निश्चित करे। क्या ऐसी इकोनोमी के लिए हम तैयार हैं? यह कैसे संभव है कि क्षेत्रफल बढ़ता जाए और कीमत भी बढ़ती जाय। अगर कीमत वास्तव में गन्ने की कम है तो किसान गन्ना क्यों बोता चला जा रहा है?

श्री कल्पनाथ राय : आपकी स्वतंत्र पार्टी का आदर्श है।

श्री भानु प्रताप सिंह : आपको तो कभी भगवान बुद्धि देगा तो चार वर्ष के बाद आपसे बात कर लेंगे।

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही सवा दो बजे तक स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at thirty three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at eighteen minutes past two of the rlock, Mr. Deputy Chairman in the Chair.

श्री उपसभापति : एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं हैं क्या ?

श्री भीष्म नारायण सिंह (बिहार) : कालिंग अटेंशन चल रहा है अभी। राज्य मंत्री कहां पीछे रह जाते हैं बराबर।

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : आ रहे हैं।

श्री उपसभापति : तो स्पेशल मैंशन शुरु कर दें।

SHRI INDRADEEP SINHA (Bihr r)): We will wait for the Minister to *ainc.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Otherwise we will take up special mentii i .

SHRI V. B. RAJU : I think the Mir i*~ ter is under a wrong impression prolH I ly. He must have thought that the Culling Attention was over. I think he is carrying that impression.

SHRI INDRADEEP SINHA : tie should be informed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN ! He h as come-

SHRI MAHENDRA MOHAN MISHRA (Bihar) : You are late.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: I am sorry for that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : New you can start.

SHRI INDRADEEP SINHA : Sir, the honourable Minister was making a comparison between the record of the Congress and the record of the Jatata Party on the question of sugar and sugar cane. I do not want to go into details. I only want to state that the policies of the Congress^ also flowed basically from the interests of the sugar barons and the Janata Government is no different. I miy remind, Sir, that at the AICC session at Bombay, the Congress had adopted a resolution to nationalise the sugar indust 1 ; and the State Assemblies of UP and Bihar also had adopted resolutions recommending to the Government of India nationalisation of the sugar industry. But sugar was never nationalised. Not only that. The cane grower was no t paid, not to speak of a remunerative price, but even a tolerable price before 1967. Only when in 1967 the Congress Party was defeated in the majority of the Northern States that the price was raised from Rs. *y* 37 per quintal to Rs. 12 or Rs. 13 per quintal. So, this lesson the peasants have to reunder.. stand. If they have to get a remunerative price, they have to defeat the Government. Unless the peasants defeat the Government, they cannot get a remunerative price.

Now, Sir, I will come to the record of the Janata Government. How did they begin ? The honourable Minister has stated that they granted some Excise relief. But the Excise relief was granted in three stages. Firstly, when the cane season started last year, the mill owners refused to open their mills. They pressurised the Government and got some concession and then they started cane-crushing one month later. The Government were aware that they were going to have a bumper sugarcane crop and so early crushing was necessary. But, instead of having early crushing, crushing started one month later which aggravated thecrisisforsugarcane. Then, Sir, the honourable Minister was saying: "You tell me a mill which paid a lower price than that fixed by the StateGovern-ment." I was at Padrauna in U.P. which the honourable Minister knows. From the 21 st February, from the midnigh of the 20th February, the mill owners refused to pay the price fixed by the State Government and they cut down the price L) Es. 4 per quintal. There was a strike in scvcial mills and the cane grcwers refused test j j Jy cane. There was a wide-spread pgitatit n. The UP Cane Minister w.n.e rusl.irg to Delhi and, after a series of nege tu.in i s, the mill owners agreed to re-cpen the mills and to pay the price fixed after the Cc-vernment had agreed to give a further relief, a further cut in the Excise duty. The Excise duty, so far as I remember, w as reducedfrom 45 per cent to 27'5 per ce i 1 on what is calhd the "free sale sugar." Then, Sir, a third concessicn was made when the ex-factory average price cf "li\y sugai" wasincreasedfrcmRs. i6£perqu:i -tal to Rs. 187-50 per quintal. That v as the third concession and, Sir, the feuith concession was made frcm the 1st of \5ay when the mills were assured that they would get a special rebate in Excise duty for late crushing. So, the Gcverrmcr.t have always been giving thi m cencessiers and the present decontrol is enly the legicj 1 result of the policy that has teen putted by this Government ever sirce tie t;re season has started in November last ycat.

Now, Sir, sugar has been ccrrrletely decontrolled. We were also dcrr.fr. dirg the end of the dual pricing system. But what did wevam ? YV? wanted that the entire producticn of sugar mills srculd be taken over by the Gcveirmcnt ard distributed tint ugh the public distiilu-tion system so that everyhedy gels sir EJ at a fixed price. This the Gcvcirrr.ert wen not prepared to do, because the mill < wr.e ftwanted at least 35 per cent of their steeksto be sold in the "free market" which wasnoth'ng but a black market where they could earn b'gger prcfits.Why should that system be rcnf'nued ? When that was not possible, when pr-'ces begin falling, then they had decontrolled the whole th'ng. Now, the hon. M'n'st(r I as argued that th's decontrol w'l! benefit tie consumer as well as the cane grrvcr. I disagree with this view, ar.d I will pt\c how his con ten tic n is wrcre and hew tie contenticn made by other hon. Members of the House en this issue is eerie ct.

Now, Sir, let us take the ccnsvrjter. "lie hon. Minister stated—I rm just qnctirg his figures —that the weighted averrge price of sugar, both levy as well as ficc sale, in November 1977, worked out to Rs. 2-90 per kilogram. Since then, the excise duty has been reduced. So, ft gar price today, when the centre-Is have leen lifted, should be lower than Rs. 2-ro] 11 kg. at least by the amount cf excise duty that has been written off,that hrs leen reduced. But that is not so. Sugar is not available even (gBs. 2-co fer 1 g. ir the retail market. The Maharashtra V ill-owneis* Association has decided"- I < e rot want to read out frcm the pcrcr—that they will not sell their sugar bele *v*, Rs. SlJ

[Shri Indradeep Sinha]

per q lintal ex factory. Then, with 17 1/2 p?r teat excise duly now, and all the handling and transport charges, at what price will it w jrk out ? Sir, the question of scarcity of sugar in West Bengal has b -en raised in the A Srit Bazar Patrika in bjnnir headlines, that sagar disappears IV j;n t'r>e Bengal market. The hon. Minister will say that it is a temporary pheno-miroi. M iyb\ it is a temporary pheno-IIIMM. Bat ev.;n temporarily sugar has diiiii-ared and prices arc rising although ths g-n-ral trend for the prices is to fall. S 1 ; i *he,* sugar will be available at what the Minister says Rs. 3 per kg.

SHRI 3-TWJ Pl\ TAP SINGH : Less than three rupees.

SHRI INDRADEEP SINHA : Some time ago, a semi-official communique or a senv-official news, or officially inspired news appeared in the Press thatsugar would be available at Rs. a- 75 per kg. He says, sugar wiil be available at the rate of Rs. 28V per quintal or so. Then, what is the result ? Who gains and who loses ? Now, 63 p?r cent of the p-oduclion *ramus* export wn WysTjir—aearly two-thirds. So, if i.v>-thirds of sugar was honestly distributed—I do not say it was honestly distributed, there was a lot of black-marketing and he admitted that levy sugar was leaking out in the free market when that thing was there —if this was honestly distributed, then tw.<-thirds of sugar was being sold, at Rs. 2.30 per kg. Now, that will be sold, according to his version at Rs. 2.80 per kg. at least. So, by 50 pa-se per kg., the p-ice will rise, that is by Rs. 500 per tonn». Let his Department workout what would bj the total cost to the consumer. It w >uld not be less than Rs. 200 crores as the m'ninvim—may be even Rs. 300 crores. The onsitTi^r will have to pay extra. To w'lom ? Nit to the G >vernment, but to thi surv millowners, Or the sugar mill-own ^rs will gain additionally Rs. 200 crores or Ri. 300 crores, as a result of decontrol of sugar.

Sir the Government have a quota of ex inning 6 1/2 lakh tonnes of sugar. Now, at w't« price will they purchase that comnidity ? F>rm>rly they could get that conm>dity at the levy price. Aveiage levy price was Rs 187-50 ex-mill. Now, they will have to purchase at Rs. 215 or something like that from the mills. So, the Government will have to pay more to the mill-owners even for the export quota. What would be the result ? Already, the export is being subsidised The international price of sugar is about Rs- *1* • 50 per kilogram. In London market, the latest quotation is £ 97 per tonne, i. e. nearabout Rs 1-50 or Rs t-55 per kilogram. So, we procure that sugar at a higher price and the Government pays subsidy out oi tax-payers' money Now, the Government will not be able to purchase sugar for export at Rs I 87 per kilogram. They will have to pay the black-market price which our mill-owners will charge That will mean extra burden on the exchequer. The tax-payers will have to pay more. Up-to 15th of August, dual price system was prevalent. Why could the Government not take 61/2 lakh tonnes before 15th August ? If they had taken the entire export quota for die year before 15th August, they could have saved several crores of rupees. But they have not done that. They are not bothered about that. It is the tax-payers' money and they will gift it to the mill-owners. So, even the exchequer will suffer. Sir, I do not know whether the estimate is correct. But die Economic Times has reported that Rs. 30 crores have been set apart in this year's budget as subsidy for the export of sugar. *(Time bell rings)* The report says that Rs. 30 crores may not be sufficient and more money may have to be allotted. The hon. Minister will tell us what would be *the* additional subsidy on the export of 6 1/2 lakh tonnes of sugar.

Then, Sir, I come to the sugarcane growers. He says that according to the Bhargava formula, the sugarcane growers in South India were getting 50 per cent share of the profits of the mills and, therefore, they were having a lower price at the time of purchase of sugarcane and a subsequent payment when the accounts were finalised. But this system did not obtain in North India. Here, taking into account the profit-sharing, the minimum price was fixed in die very beginning and it was all paid at once to the sugarcane growers. Now, what price was paid ? This is from the report of the Sugar Mill-owners Association and I do not think they will hide facts. According to the Sugar Mill-owners' Association, in Maharashtra the minimum price paid to the sugarcane growers was Rs. 17-35 in 1975-76, Rs. 16-60 in 1976-77 and Rs. 16-20 in 1977-78 I do not want to read the figures about odier States. Now what have the North Indian sugarcane growers got ? In Western Uttar Pradesh where the price was die highest, it was Rs. 13-25 in 1975-76, Rs. 13-25 in 1976-77 and Rs. 13-50 in 1977-78.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI : Please tell us the comparative recovery also.

SHRI INDRADEEP SINHA : The percentage is 9-5 in Punjab, 9-39 in Haryana, io- 25 in Western U.P. and 11 16 in Maharashtra. If you are interested, I can read the whole thing. I have got the chart with me. Coming to cane price,

as against Rs. 13- 50, now the Government say that growers will be paid Rs. 10. Therefore, the sugarcane growers at least of North India will lose at the rate of Rs. 3-50 per quintal I think in South India also they will lose. Except perhaps the coopera-tive societies, the others are not going to pay more than Rs. 10. What would be the loss this year ? According to Government figures, 68 million tonnes of sugarcane has been crushed by the sugar mills. So, if the loss is even Rs. 3 per quintal or Rs, 30 per tonne, it will come to more than Rs. 200 crores. So, the consumer will lose Rs. 200 crores, the exchequer will lose Rs. 50 crores, the cane-grcwer will lose Rs. 2C0 crores And where will this money go ? This will go to sugar mill owners.

Now, this Government says that the entire policy of the Congress Government in the post-independence pericd was anti-peasant, anti-rural India, pro-urban and pro-capitalist. They say that they are pro-peasant. Now, this is how they are proving to be pro-peasant. They have cut down the price of sugarcane and they have transferred that money to the sugar mill-owners. Now, the cane-grower may labour in his field. He may produce the sugarcane. But all the profit, all the surplus that he produces, will be transferred to the sugar mill owner through the agency of this Government, its policy and its mechanism. This is how this Government has thoroughly betrayed the interests of the peasantry.

Now, Sir, what about the cost of sugar-cane ? Last year—the hon. Minister will contradict me if I am wrong—the Agricul-tural Prices Commission recommended that the minimum price of sugarcane for a recovery of 8- 5 per cent be fixed at Rs. 9-50 per quintal. That was their recommendation. The Government did not accept it. Why did the Agricultural Prices Commission make this recommendation ?

श्री उपसभापति : कृपया संक्षेप में बोलिये ।

श्री कल्प नाथ राय : श्रीमन्, बोलने दीजिए, यह गंभीर मसला है, किसानों की लूट हो रही है ।

श्रीमन्, मैं अभी खत्म कर रहा हूं ।

SHRI INDRADEEP SINHA : They said, and I quote :

"While deciding upon the appropriate level of the statutory minimum price for sugarcane payable by the sugar fac-, tories in the ensuing season, the Com-mission has examined the latest data of cost of production of this crop, as avail-able from the Government records ...

The estimate of cost for a quintal of sugarcane works out to Rs. 8-50 and Rs. 7-65 in the case of Punjab and Uttar Pradesh respectively for 1975-/6."

And on this basis, they recommended a minimum price oi Rs. 9-50 last year. Last year, the Government did not accept it. This year, they have raised it to Rs. to. By raising the price to Rs. 10, they are simply implementing the reccn mer.daticn made by the Agricultural Prices Ccir mission last year because, since last year, the cost of cultivation has further gtne up? By how much it has gone up ? I will just mention a few items : Diesel oil has increased by 1-3 per cent; clelctricity has increased by 11-3 per cent; cement has increased by 7-9 per cent ; pig iron has increased by 4- 1 per cent ; tractors have increased by 8-2 per cent ; seme agricultural machinery by 5 per cent; and agricultural sprayers by 1 • 8 per cen t So, the cost of all these items has gone up. So, if they are now proposing a price of Rs. 10 per quintal, they are simply carrying out the recommendation of the Agricultural Prices Commission made last }car. But last year, in addition to the ATC recommendation, according to the Bhargava formula, there was a profit-sharing in South India and there was an additicr.al payment in North India. Will that continue ? Will the cane-grcwer get anything more than Rs. 10 per quintal it 1 a recovery of 8-5 per cent ? And if they get, what will that be ? Why do not the Government say so ?

Lastly, Sir, according to reports appearing in the press, about 32 lakh tonnes of sugar will be the carry-over stock at the end of the current sugar season. Out of these 32 lakh tonnes, what would be the levy sugar ? When the Government was going to decontrol sugar, they could easily have taken their quota of levy sugar ficm the mills before liftirg the ccntroh. '11 c mill-cwners were shouting that ycu please purchase seme sugar and create a buffer stock. What was the difficulty in Go-vernment purchasing 65 per cent of these 32 lakh tonnes or whatever was the levy quota from the mills and selling that sugar at the old price of Rs. 2-30 per Kg. through the public distribution system ? He says the stock with the mills could suffice for 11 months. If not for 11 months, at least for six months the people could have got sugar at a cheap price Thus, what the people were entitled to get at Rs 2' 30 per Kg that also has been handed over to the sugar mills so that they can sell it in the black market. So, this Govern-ment is simply an agency of the black market. It just serves the interest of the black marketeers; it safeguards their interest ; it cheats the peasants; it cheats the consumer and it cheats the sugar mill workers also, because now the production will decline and the factories will cut down the employment. More sugar cane will

[Shri Indradeep Sinha]

be burnt next year and more sugar mill workers will be rendered unemployed. This is going to happen. So this policy of the Government of decontrolling sugar is against the consumers and against the producers of sugar cane and also against the sugar mill workers.... ?

श्री कल्पनाथ राय : वह पूंजीपतियों की सरकार है ।

SHRI INDRADEEP SINHA : In whose interest it is ?

SHRI KALP NATH RAI : It is in the interest of capitalists.

SHRI INDRADEEP SINHA : It is in the interest of sugar mill-owners because they collect money from these sugar mills.

श्री कल्पनाथ राय : चीनी मिल मालिकों के एजेंट हैं ।

SHRI INDRADEEP SINHA : This policy has to be rejected and if the Parliament—because of majority of these people —is not able to reject this policy, I am sure the cane growers will reject it by defeating the Janata Party in the next elections as they rejected the policy of the Congress Government by defeating the Congress Party in the last elections.

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन, बहुत सी बातें दोहराई गई हैं इसलिये मैं सब का उत्तर नहीं दूंगा । एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह दोहरी मूल्य प्रणाली इस बात पर आधारित थी कि खुले बाजार में जो अनुमान लगाया गया था कि वह कीमत मिलेगी, वास्तव में जब सरकार निश्चित करती है कि 13 रुपये या 12 रुपये मिलेंगी तो उसके अंदर यह आश्वासन निहित है कि फाक्टरियों को खुले बाजार में चीनी का अमुक भाव मिलेगा । यह एक प्रकार से एग्रीमेंट सा समझिये । यह संभव नहीं है कि जिस आधार पर यह सारा हिसाब लगाया जाता है, वह हिसाब अगर गलत हो जाए तो भी लेवी शुगर उसी कीमत पर मिलती रहे । मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो लेवी शुगर 65 फीसदी ली जाती रही है वह कास्ट आफ प्रोडक्शन से कम पर ली जाती थी । आज पूछा जाता है किस के इंट्रेस्ट में है यह डि-कंट्रोल । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो उल्टी-पुल्टी नीतियां चलती रहीं है जिसके अन्तर्गत 65 फीसदी चीनी कास्ट आफ प्रोडक्शन से कम पर ली जाती रही, केवल इसलिये कि शहर के कुछ लोगों को सस्ती चीनी दी जा सके । इस नीति को समाप्त करके इंडस्ट्री को फिर से साउंड बेसिस पर लाने के लिये डिकंट्रोल की आवश्यकता थी । मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सी बुद्धिमत्ता की नीति है कि जिस चीनी को पैदा करने की कोस्ट 215 से 225 रुपये तक है, उस को 169 और 187 पर ले लिया जाए । मैं बताना चाहता हूं कि पीछे 169 पर भी ली जाती थी । अगर इतनी कम कीमत पर, कोस्ट आफ प्रोडक्शन से कम कीमत पर ली जाएगी तो जरूरी बात है कि खुले बाजार में चीनी महंगी बिकेगी । मैं यहां आंकड़े नहीं दे सकता अगर मैं आंकड़े देता हूं तो कल को यह इज्लास में एवीडेंस बन जाएगा, मैं इतना कहना चाहता हूं कि उनको हक है वह यहां आ कर कहें कि फिर से, दुबारा से रिवाइज करें, लेवी शुगर के दाम बढ़ायें । उपसभापति जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको समझा सकता हूं, किसी माननीय सदस्य को समझा सकता हूं, लेकिन अगर वह आंकड़ें यहां स्पष्ट कर दूं तो वह कल के दिन इजलास एवीडेंस बन जाएगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि ये दोनों बातें संभव नहीं हैं (*Interruptions*) । लेवी शुगर के बारे में बता रहा हूं कि पूरे साल जब हम उनको खुले बाजार में, जिस भाव पर हमने उनको आश्वासन दिया था, नहीं दिला सके तो । हमें कौन-सा नैतिक अधिकार रह जाता है कि हम कास्ट आफ प्रोडक्शन भी न दें और उन चीनी मिलों को ले लें और अगर हम उन मिलों को अपने हाथ में ले ले तो इस में भी संदेह है कि वे मिल अक्तूबर या नवम्बर तक भी चल सकें । आज भी सारे परिवर्तनों के बावजूद इसमें संदेह है कि जो मिल बहुत ही कमजोर हैं, जैसे बिहार और

पूर्वी उत्तर प्रदेश की तथा देश के दूसरे राज्यों में इस प्रकार की मिलें हैं जो हाई कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन मिलें कहलाती हैं, जो पुरानी मिलें हैं वे चलेंगी या नहीं। मैं इन बातों को पहले ही कह चुका हूं, लेकिन आप उल्टी बात कह रहे हैं और कहते हैं कि हमने उन मिलों को सहायता देने का कोई वरदान दे दिया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि स्टेट सेक्टर में, चाहें उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रबन्ध में हों या बिहार सरकार के प्रबन्ध में हों, बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। हरियाणा की चीनी मिलों का हवाला में पहले ही दे चुका हूं। उन्होंने लिख कर नोटिस दे दिया है कि अगर उनको तीन करोड़ रुपयों का अनुदान नहीं दिया गया तो वे मिलें बन्द हो जाएंगी। इसलिए अगर आप इस प्रकार से मिथ्या प्रचार करेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

LH

श्री कल्प नाथ राय : स्टेट सेक्टर में मिले हैं उनकी हालत कैसी है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनकी हालत भी बहुत खराब है। वे घाटे में चल रही हैं।

एक बात यह भी कही गई कि अखबारों में तीन सौ करोड़ रुपयों की बात आई है और इस बारे में इकनोमिक टाइम्स का हवाला दिया गया है। इकनोमिक टाइम्स ने स्वयं इस समाचार को कंट्रेडिक्ट किया है और कहा है कि गलती से 300 करोड़ रुपये छप गया था। यह केवल 30 करोड़ है। इसके अलावा एक बात यह भी कही जाती है कि 10 रुपये गन्ने की कीमत मिलेगी। मैं इसको बारबार स्पष्ट कर चुका हूं। 10 रुपये की कीमत साढ़े 8 फीसदी रिकवरी पर है। अगर रिकवरी लगभग 10 परसेंट है तो कीमत 11 रुपये 77 पैसे होती है। इसके बावजूद भी अगर चीनी मिलों को मुनाफा होता है तो उस मुनाफे का आधा शेयर उनको मिलेगा। भार्गव फारमूले के अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था है। जब 10 रुपये की बात कही जाती है तो जहां जिस प्रकार की रिकवरी होगी उस मुताबिक 11 रुपये 75 पैसे या 76, 77, 80 या 90 पैसे मूल्य होगा।

श्री प्रकाश महरोत्रा (उत्तर प्रदेश) : मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश एवरेज रिकवरी क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : एवरेज रिकवरी बदलती रहती है।

श्री प्रकाश महरोत्रा : आपने बताया है कि साढ़े 7 परसेंट पर 10 रुपये दाम बैठते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी हालत में एवरेज रिकवरी क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह साढ़े 9 से ऊपर नहीं है।

श्री प्रकाश महरोत्रा : यह साढ़े 9 से ऊपर है। लगभग 10 है।

श्री भानु प्रताप सिंह : मेरा कहना यह है कि यह 10 से थोड़ा कम है। आप सारा हिसाब जोड़ सकते हैं। मैंने यह बताया है कि 10 रुपये कीमत साढ़े 8 परसेंट की रिकवरी पर है। अगर 10 परसेंट रिकवरी होगी तो 11 रुपये कुछ पैसे बठेगा।

श्री कल्प नाथ राय : साढ़े 9 परसेंट पर कीमत क्या होगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : आप इसका हिसाब स्वयं लगा सकते हैं। आप अगर थोड़ा भी गणित जानते हैं तो स्वयं जोड़ लगा सकते हैं। मैंने एक सिद्धांत आपको बताया है।

श्री कल्प नाथ राय : आप जोड़ कर बता दीजिये।

श्री भानु प्रताप सिंह : आप इतना ही नहीं जोड़ सकते हैं तो मैं नहीं बताऊंगा।

श्री इन्द्रदीप सिंह : मेरे पास इसके आंकड़े हैं। मैं बता सकता हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, यह भी कहा गया कि बम्बई, दिल्ली में पहले से ही कीमत 2.80 रुपये है।

श्री कल्प नाथ राय : श्रीमन्, बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने इस शुगर डिकंट्रोल की निन्दा की है और प्रधान मंत्री को पत्र लिख कर यह मांग की है कि चीनी का पुन: कंट्रोल किया जाय।

श्री भानु प्रताप सिंह : यह सही हो सकता है, मगर मैं उनको कोई अथोरिटी नहीं मानता हूं।..... (*Interruptions*)।

श्री उपसभापति : आप पहले उत्तर आने दीजिये।

PRO?[1]. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal) : In Calcutta sugar is selling at Rs 3-40 and he is saying that it is selling at Rs- 2*80.

श्री कल्प नाथ राय : शाही जी, क्या आपकी पार्टी का कोई आदर्श है?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, मैं बड़ा साफ कहता हूं कि हम लोग इस मामले में नहीं सारे मामलों में समाजवाद से बंधे हुए हैं और हम लोगों का यह . . .

श्री कल्प नाथ राय : उपसभापति महोदय, जनता सरकार के मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है और शाही जी कह रहे हैं कि हम समाजवाद से बंधे हुए है, दोनों में से कौन सही है?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : देखिए, हमारे साथी ने यह कहा कि डीकंट्रोल मिल मालिकों के पक्ष में जाएगा। अगर यह मिल मालिकों के पक्ष में जाता तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज से चार-पांच दिन पहले मिल मालिकों ने सरकार से क्यों मांग की है कि फैक्टरी से शुगर का रिलीज डीकंट्रोल न किया जाए उस पर कंट्रोल रखा जाए। मिल मालिकों ने यह मांग की है कि फक्टरी से शुगर के रिलीज पर कट्रोल रखा जाए, इसके मायने यह हैं कि टोटल डीकंट्रोल करने पर मिल मालिकों को घाटा होगा। इसीलिए मिल मालिक परेशान हैं। अगर उनके फायदे का होता तो हरगिज वे यह मांग न करते कि फैक्टरी से रिलीज पर कंट्रोल कायम रखा जाए और टोटल डीकंट्रोल न किया जाए। दूसरी बात श्रीमन् यह है कि जैसे हमारी साथी ने जिक्र किया कि मिल मालिक यह चाहते हैं कि गवर्नमेंट बफा स्टाक क्रिऐट करे। क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि अपना सारा घाटा वे गवर्नमेंट के मत्थे थोप दें। आज जब मिलों के गोदामों मे चीनी रखने के लिए जगह नहीं है, बैंकर्ज का रुपया हैल्ड-अप है, बैंक उनकी चीनी के अगेंस्ट एडवांस नहीं दे रहे हैं तो उस समय यह चाहते हैं कि उनको लास न हो बल्कि गवर्नमेंट को लास हो और गवर्नमेंट बफर स्टाक क्रिऐट करे। तीसरी चीज, यह सही है कि एक्सपोर्ट में भारी घाटा होगा। मै इस राय का नहीं हूं कि ऐट ऐनी कास्ट एक्सपोर्ट किया जाए। जो घाटा सरकार या एस०टी०सी० एक्सपोर्ट में बर्दाश्त करेगी उस घाटे को चीनी की कीमत में एडजस्ट कर के चीनी को सस्ता बना कर उपभोक्ता को दी जाए बजाय इसके कि चीनी का ऐट लास एक्सपोर्ट किया जाए। उसमें सरकार उनको एडजस्ट करे चीनी के भावों के गिराये।

दोहरी मूल्य नीति इसलिए चलाई गई थी कि उसमें मिल मालिकों और चीनी के होलसेल को ब्लेक मार्केट में सीधी सुविधा मिलती थी। 65% जो चीनी लेवी में देते थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो गांव के लिए अलाट होता था वह सीधे बलेक मार्केट मैं जाता था। मैं जानता हूं कि मेरा गांव के आसपास के चीनी के कोटेदार को गोरखपुर के शहर से, गोदाम से चीनी जाती थी और शहर

में ही वे बेच देते थे। एक दाना भी गांव की ओर नहीं जाता था। इसलिए यह कहना कि 65 प्रतिशत चीनी जो है वह सस्ते दामों पर मिलती थी, सही नहीं है। जो चीनी शहरों में बेची जाती थी वह सस्ती मिलती थी। गांव की चीनी सारी की सारी ब्लैक मार्केट में चली जाती थी और उसका फायदा होल-सेलर्ज और रिटेलर्ज खाते थे। श्रीमन्, मंत्री महोदय का यह कहना कि मिल मालिकों को घाटा होता चला आ रहा है, वे बड़े परेशान हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मिल मालिकों को लगातार घाटा होता चला आ रहा है तो कहां से प्रदीप नारंग ने संजय गांधी को रुपया दिया, . . क्या बाहर से लाते हैं. . .

एक माननीय सदस्य : कांति को भी शामिल कर लीजिए।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : कांति का भी नाम आप ले लीजिए, मुझे एतराज नहीं है मगर मैं कहना चाहता हूं कि और मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि अगर मिल मालिकों को घाटा हो रहा है तो चीनी की मिलों का करोड़ों रुपया जो चुनाव फण्ड में पिछले बीसियों सालों से चन्दे में आ रहा है वह कहां से आ रहा है? वह घाटा उठाकर दे रहे हैं चन्दे में? इसलिए यह कन्टेशन मंत्री जी का कि चीनी मिल मालिकों को घाटा हो रहा है यह कतई सही नहीं है। उनके यहां डुअल एकाउंट होता है। एक भी प्राइवेट मिल मालिक को बताइये, उसके आफिस में चलकर जिसके दो रजिस्टर न हों। एक रजिस्टर सरकार के लिए होता है और एक रजिस्टर अपने लिए। जिसको आप आधार मानते हैं, जहां से आप कास्ट एकाउंटिंग लेते हैं कि कास्ट प्राईस यह है वह बिल्कुल झूठा होता है। चीनी की वह लागत नहीं है जिसको आप मानते हैं और जिसकी आप कास्ट काउंट करते हैं।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह है कि आज जो यह फैसला हुआ है कंट्रोल उठाने का मैं अपने मित्र कल्प नाथ राय जी से कहूंगा . . . .

एक माननीय सदस्य : पांच रुपये पर बिकेगी।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : पांच रुपये पर चीनी नहीं बिक सकती है। आप विद्वान आदमी हैं चीनी की वह दुर्गति है, चीनी इतनी गोदामों में सड़ रही है कि अगर सरकार उनको मदद नहीं करेगी तो चीनी ला-मोहाला ढाई या पौने तीन रुपये पर बिकेगी। दोस्तों ने कहा कि इस समय बाजार में चीनी नहीं है। 31 अगस्त तक का कोटा सबको दे दिया गया है. . . .

श्री कल्प नाथ राय : अगस्त में पांच रुपये बिक रही है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : जरा सुनिये, सरकार ने डी-कन्ट्रोल करने के पहले 31 अगस्त का कोटा सारे कंज्यूमर्स को दे दिया है अपनी कन्ट्रोल शाप्स के माध्यम से इसलिए आज यह कहना कि बाजार से चीनी गायब है, यह सत्य नहीं है। 31 अगस्त का कोटा दे दिया गया है, उस समय बाजार से चीनी गायब होने का प्रश्न ही नहीं उठता है . . . . (*Interruptions*) इस समय तो जैसा मंत्री जी ने कहा कि चीनी का भाव एक दिन में 45 रुपये क्विंटल क्रेश किया है। उस हालत में कोई भी व्यापारी 4–5 दिन तक चीनी का सौदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह प्राब्लम रहेगी 2–4 दिन तक मगर उसके बाद प्राईसेज स्टेबिलाईज होंगे। प्राइसज पौने तीन पर होंगे। . . .

श्री कल्पनाथ राय : प्राईसेज बढ़ेंगी ना?

डा० रामकृपाल सिंह : इनकी आदत है।

श्री उपसभापति : कृपया शांत रहिए।

श्री कल्प नाथ राय : किसानों के विषय में बोलिए।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : इसका लाभ सीधे सीधे किसानों को पहुंचेगा इसलिए कि हम इसमें इन्टरेस्टेड हैं कि किसानों को इस साल जो साढ़े 12 रुपये क्विंटल गन्ने

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

का दाम मिला है वह हर हालत में मिलता रहे। इस साल साढ़े बारह रुपये पूर्व उत्तर प्रदेश में मिला है और साढे 13 रुपये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला है, यह दाम मंत्री जी घटना नहीं चाहिए, यह दाम घटेगा तो आपकी सरकार में हम लोग सत्याग्रह करेंगे और जेल जायेंगे। कांग्रेस सरकार में भी दर्जनों बार गये हैं आपकी सरकार में भी जायेंगे और किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यह फारमूला एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मिल मालिक को घाटा हो रहा है। अगर मिल मालिक को घाटा हो रहा है तो क्यों नहीं वे अपनी फक्ट्री को आपको हैण्ड-ओवर कर देते हैं, क्यों नहीं केन ग्रोअर्स को मजदूरों को हैण्डओवर करते, क्या लाभ उठाकर कोई रोजगार करता है। उनको ये प्रेशर टेक्टिक्स हैं जो वे पिछले 30 सालों से एडाप्ट करते चले आ रहे हैं, उसी प्रेशर टेक्टिक्स के अनुसार उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार से छूट ली, उसी टेक्टिक्स के अनुसार उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार से छूट ली, उसी टेक्टिक्स को एडाप्ट करके अब वे फिर छूट चाहते हैं (*Interruptions*) परन्तु अब वह टेक्टिक्स नहीं चलने पायेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दक्षिण में कोआपरेटिव मिले हैं, आन्ध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, है। जहां कोआपरेटिव मिले हैं वहां 16 और 17 रुपये का प्राफिट शयरिंग स्कीम चलती है। हमारे यहां जहां नारंग की मिले हैं, मोदी की मिलें हैं, यह लोग कुछ पसा नेताओं की पाकेट में रख कर किसानों को, मजदूरों को लूटते हैं। यह नहीं चलने पायेगा। मेरी सीधी-सीधी मांग यह है कि अगर घाटा हो रहा है हमारे मिल मालिकों को, तो वे अपनी मिल केन-ग्रोअर्ज को, मजदूर को दे दें। घाटे का सौदा मत करो। मजदूर चलायेगा मिल को।

श्रीमन्, सारी कोशिशों के बावजूद आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों और गन्ना-ग्रोअर्ज का करोड़ों रुपया हमारे मिल-मालिक दबा कर बैठे हुए हैं। मुझे याद है कि जब पं० कमलापति त्रिपाठी जी चीफ मिनिस्टर हुए थे, वे खड्डा में गये। खड्डा के चीनी मिल मजदूरों का 90 लाख रुपया बाकी था, कई महीनों की मजदूरी लगातार बाकी थी। मजदूर बेचारे मजबूर थे। काम बन्द कर दें, तो नौकरी चली जायगी। पंडित जी के पास जब वे डेलिगेशन ले कर इस भरोसे के साथ आए कि मंत्री जी आये हुए हैं, सहायता करेंगे तो पंडित जी ने कहा कि क्या कोई थैली ले कर आये हैं कि तुमको बांट दें। मजदूर निराश होकर चले गये। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि मिल-मालिक की चीनी में कितना रस होता है, मैं देखता चला आ रहा हूं पिछले तीस साल से कि सारे लोग जो सरकार में आते हैं उन को वे बहुत प्रभावित करते हैं। यहां तक कि उनकी दिल्ली में लाबी है। हमारे मित्र श्री प्रकाश मेहरोत्रा वहां बैठे हुए हैं। वे भी कभी उस लाबी के रिप्रेजन्टेटिव थे। चीनी मिल मालिकों की लाबी जो दिल्ली में है वह यहां काफी पैसा खर्च करती है। संसद सदस्यों और दूसरों को प्रभावित करने के लिये पैसा कहां से आता है? तो, मैं कहना चाहता हूं कि इस डी-कण्ट्रोल से दो क्लास का सीधा-सीधा फायदा हुआ है। एक तो केन-ग्रोअर्ज का कि उनको गन्ने का दाम मिलेगा और मिल चलेंगी और दूसरे मिल मजदूरों का। अगर फैक्ट्री बन्द हो जाती तो लाखों मजदूर बेकार हो जाते। इसलिये लाजमी था कि ऐसी परिस्थिति पैदा की जाए जिसमें किसान को भी फायदा हो और मजदूर को को भी फायदा हो और यह ब्लेक-मार्केटिंग जो भारी स्केल पर पूरे देश में चल रही थी, वह समाप्त हो। डयूअल प्राइसिंग जो थी वह ब्लैक-मार्केटिंग की जड़ थी। इसको समाप्त होना बहुत जरूरी थी और यह डयूअल प्राइसिंग सिस्टम मिल-मालिकों के इशारे पर कायम किया गया था। उस से न किसानों को फायदा था न मजदूर को।

SHRI KALYAN ROY(West Bengal) : We shall lake up the Appropriation Bill tomorrow, Sir.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन, मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि वे साफ-साफ शब्दों में आश्वासन दें कि पिछले साल जो गन्ने का दाम किसानों को मिला, उस में कोई कमी नहीं आयेगी। दूसरा यह कि मंत्री जी आपने आज पांच पैसे रिवाइज किया है। आज से पहले आपने जो इस हाउस में और बाहर स्टेटमेन्ट दिया उस में आपने 2रुपये 75 पैसे की बात कही थी कि चीनी रु० 2. पैसे 75 पर ही बिकेगी। आज आप 2-80 रु० पर पहुंच गए।

श्री भानु प्रताप सिंह : नहीं पहुंचे। वह तो उन सदस्य ने कहा था।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : तो मैं सिर्फ यह आश्वासन चाहता हूं कि अगर चीनी का भाव 3 रु० को पार करेगा, तो सरकार चीनी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करेगी। आप इसका पूरा आश्वासन दें और यह बात मूल:भूतत: स्वीकार करें कि चीनी को भी अंतत: पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के अंदर आना चाहिए। यह एक मूल बात है जिस को आप इग्नोर नहीं कर सकते और न हम सिद्धांत से आगे कोई बात मानने को तैयार हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन, यह बात तो सच है कि जितने भी चीनी उद्योग से लगे हुए हैं, चाहे वे कोआपरेटिव सेक्टर में हों, चाहे प्राइवेट सैक्टर में हों, चाहे पब्लिक सेक्टर में, सब की मांग थी कि कम से कम रिलीज पर सरकार कंट्रोल रखें—आज इस तरह के सैकड़ों तार और प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन उस को नहीं माना गया।

श्री कल्पनाथ राय : बधाई।

श्री भानु प्रताप सिंह : अब उन को तो यह नहीं मालूम कि कब बधाई देनी चाहिए। पहले वह शेम कह रहे थे। अब वही बधाई कर रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बफर स्टाक के लिए भी सरकार कोशिश कर रही है कि अगर 10 लाख टन का बफर स्टाक बने। वह अपनी चीनी से छुटकारा लेना चाहते हैं फिर भी सरकार ने माना। वास्तव में स्थिति यह है कि डयुअल प्राइसिंग इतना मस्ट था—एक तो उनकी पार्टी पैसा लेती थी और दूसरी तरफ उन के कार्यकर्ता ही गांवों में चीनी के लाइसेंस प्राप्त किए हुए थे, वह सिलसिला टूट रहा था और इस से उन को ज्यादा तकलीफ़ हो रही है . .

श्री कल्पनाथ राय : किसको ?

श्री भानु प्रताप सिंह : डयुअल प्राइसिंग के टूटने से बहुत से गांवों के, कारखानों के जो कांग्रेस के कार्यकर्त्ता थे उन को तकलीफ पहुंचेगी।

(*Interruptions*)

श्री कल्पनाथ राय : नहीं, नहीं, चौधरी चरण सिंह ने 5 करोड़ रु० पूंजीपतियों से लिया।

श्री प्रकाश महरोत्रा : कौन फूड मिनिस्टर थे जब यह डयुअल प्राइसिंग पालिसी लगायी गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : अब मुझे उत्तर दे देने दीजिए।

श्री प्रकाश महरोत्रा : बाबू जगजीवन राम नहीं थे क्या ?

श्री भानु प्रताप सिंह : एक मिनिस्टर के किए से नहीं होता, पूरी कैबिनेट का फैसला होता है। श्रीमन, मुझ से आश्वासन मांगा गया—एक तो मूल्यों के बारे में। "यह आप जानते हैं, हम लोगों ने रु० 2.75 का भाव कहा था और उस पर ही अभी कायम हैं जब एक माननीय सदस्य ने पूछा क्या 2-8।

[श्री भानु प्रताप सिंह]

रु० से ऊपर नहीं बढ़ने पाएगा, तो मैंने कहा, नहीं बढ़ेगा । हमारा लक्ष्य रु. 2-75 प्रति किलो का है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दस-पांच पैसे इधर उधर हो सकता है । परन्तु अगर 3 रु० से ऊपर होगा तो जरूर कंट्रोल होगा । "

अब जो यह कहा माननीय शाही जी ने क आपके आंकड़े के आधार क्या , आमदनी खर्च का, तो मैं तो बता सकता हूं कि हमारे 3 आधार हैं—एक तो ब्यूरो आफ कास्टस एण्ड प्राइसेज, दूसरे, जो सहकारी चीनी मिलें हैं उनका कारोबार ; और तीसरे जो सरकार के सीधे नियंत्रण में हैं उनका कारोबार । छः चीनी मिले जो उत्तर प्रदेश सरकार के ही हाथ में हैं, जो नेशनलाइज की जा चुकी हैं, उन में 12 करोड़ का घाटा हुआ है ।

श्री नागेश्वर प्रशाद शाही : मिसनेजमेंट है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : हमको अच्छे मैनेजमेंट का कहीं नमूना दिखलाइए । दूसरी बात उन्होंने कही कि आप नहीं चला पाते हैं तो मजदूरों को दे दीजिए । कारखाने बंद पड़े हुए हैं, मैं आमंत्रित करता हूं : आप मजदूरों को, किसानों को तैयार करिए वे कारखाने दिला दिए जाएंगे । आन्ध्र प्रदेश में, बिहार में हैं । इसका कोई प्रश्न नहीं है . . .

श्री इन्द्र दीप सिंह : हमारे यहां एक कारखाना बंद पड़ा हुआ है, बैंक का रुपया बाकी है, किसानों का रुपया, मिल मजदूरों का रुपया देना बाकी है . . .

(Interruptions)

श्री उपसभापति : कृपा कर के शांति रखिए ।

श्री कल्पनाथ राय : अरे, किसानों का नाश मत करो भाई ।

श्री भानु प्रताप सिंह : किसानों का लाभ होने वाला है । आप लोगों के राज में । उनका बहुत अहित हो गया है । अब उनको सही बात बतायी जा रही है । आप लोगों ने जो यह इतने दिनों तक रखा, अब वह चलने वाला नहीं है । चीनी सस्ती मिलेगी इसका मैं आश्वासन दे चुका हूं । गन्ने की कीमत के बारे में मैं कह चुका हूं कि दस रुपया 8.5 रिकवरी से लिंक हो कर उस की कीमत रहेगी । वह साढे ग्यारह या पौने बारह तक जा सकती है । अगर किसी ने मुनाफा किया तो उस में से आधा मुनाफा किसान को मिलेगा और यह भी संभव है कि राज्य सरकारें अपना परचेज टैक्स कुछ कम कर दें । क्योंकि यह परचेज टैक्स तब लगाया गया था कि जब चीनी के भाव ऊंचे थे। यह भाव अब नीचे आ गये हैं लेकिन कुछ राज्य सरकारें आज भी दो रुपये क्विंटल तक ले रही हैं । अगर वह इस काम को समाप्त कर दें तो वह किसानों को पास हो सकता है। अगर हर सरकार टैक्स लगाती रहे और किसानों की दुहाई देती रहे तो मुश्किल होगी। यह आश्वासन मांगा गया कि पिछले वर्ष जो मूल्य था उससे कम नहीं होगा तो उस संबंध में मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि अगर चीनी पिछले वर्ष के भाव पर बिकेगी तो वही मूल्य मिलेगा, लेकिन अगर चीनी का भाव कम हुआ तो गन्ने का भाव निश्चित रूप से कम होगा ।

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE (West Bengal) : Mr. Deputy Chairman, I am really shocked to hear the Hon. Minister speaking for the tncocf olists and the industrialists.

Whatever arguments he puts forwfard and whichever way he defends the industrialists, the fact remains that the'policy

of decontrolling sugar by the Central Government has served only the interests of the monopolists, the big industrialists, the black-marketeers and the profit-makers, and it goes against the interests of the workers, the peasants, the common people and the millions of the consumers.

The Government has not only decontrolled sugar, it has also withdrawn the levy and declared the relaxation in bank loans and tax. AH these things together show that the Government is only going to serve the haves and not the have-nots.

Now, after bowing down to the wishes of the monololy businessmen, the price of the sugarcane ha3 been declared at Rs, 10 from Rs. 8.50 or something per quintal. This is only face-saving and a show. Just as one of my friends has already pointed out that on calculation the minimum cost comes to Rs. 16,1 have a document here, a statement by the West Bengal Kisan Sabha, which shows that nothing less than Rs. 15 will cover the just cost, per quintal of the sugarcane for the sugarcane growers. Increasing the cost per quintal from Rs. 8 to Rs. 1 o is not a solution at all.

The Hon. Minister said that if the cost of sugar goes beyond Rs. 3, they will again control it. Then, what is the use of decontrolling it, I cannot understand.

At the beginning, tthe Hon. Minister said, "Please do not inject politics in it." I wonder what he calls politics and what he does not call politics. If he takes a decision in the interest of the industrialists, the monopolists and the sugar mill-owners and deprives the workers, the peasants, the common people and the millions of the consumers, it is not politics, but if we speak something* in the interest of the people, it i3 politics. This is a very funny argument. Such argumnts, the ruling' people have given many times.

Now I would like to state here the reactions, if you want to know. We have known reactions from various States, especially from West Bengal. The Chief Minister, Mr. Jyoti Bosu, has already given a statement against it. He and Mr. Ashok Mitra, the Finance Minister, both of them, are in Delhi at present. Maybe, they are discussing the issue with the proper, authorities. Not only that, but the Cabinet of the Left Front Government has also issued a statement against it. They have expressed their deep anxiety over it. The Left Front Committee has taken a. decision against it. And not only that, mass organisations like the Kisan Sabha, trade unions, women's organisations and various other organisation ; are launching a movement against it. I am from West Bengal. We have the bitterest experience of commodities of daily use disappearing from the market after the declaration of decontrol. Now, it has already happened. In some of the villages, it has already started disappearing. In Darjeeling, my friend here is telling me, sugar has already disappeared from many places. This is a funny mathematical fallacy to say that the controlled rate was Rs. 2.30 and in the open market, the price was jomething like Rs. 3.40 or Rs. 3.50 and we find out a mean and that is Rs. 2.75 and in any case will not go beyond Rs. 2.80. One of the hon. Members has already asked in whose interest it will go. In the interest of the millions of consumers ? No. They do not buy from the open market. They get sugar only from the ration shops. They get it at Rs. 2.30. They constitute 80 per cent of the people. For them, the price is definitely increasing. And it will not remain at Rs. 2.75 or Rs. 2.80,1 am telling you, because we have a long experience, during war-time and after war-time, dining Emergency and after Emergency, that whenever decontrol takes place, the commodities sugar and everything, disappear from the market. For the time being, the prices may not be so high, but after some time, the commodities will disappear.. ..

SHRI KALP NATH RAI : Black marketeers.

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: . . . .from the market. This has happened in the case of groundnut oil, baby food and other commodities of daily use. In West Bengal we have had the bitterest experience. After that, you get it from the black market at a much higher price. So. there is no use of face-saving or eyewash here. There is no use of saying "We will not allow the prices to go up," They will go up,, They have decided on decontrol for getting the price higher; that is the truth. Now the Central Government must have got by this time the memorandum from the State Government of West Bengal requesting die Centre to give at least the agreed quota of sugar to our State so that we can give to our people through the fair-price shops at reasonable prices, at the controlled prices. The West Bengal Government made this request long before. And now they are still requesting mat more and more commodities of daily use should be taken under Government control and distributed through the fair-price shops at controlled rates. They have named 8/10 commodities of daily use. Instead of moving in that direction die Central Government is decontrolling sugar one

[Shrimati Kanak Mukherjee] of the most vital and essentia, commodities- In whose interest does it go ? It goes without saying that once more the Janata Government has bowed down to the wishes of the monopoly businessmen. So by whichever argument they may try to defend their decision the people in general are against it Coming from West Bengal I can say that the Government of West Bengal is againit it; the Left Front Committee is against it; the masses of people are against it; mass organisations and representatives of people are against it; and we the MPs representatives of the people, are against it. Similarly, you have got similar reactions from many other States. So I request the Central Government to revise their decision, taking into consideration the reactions of the common people and the representatives of people But if they do not react to the reactions jf the millions of people, of the representatives of millions of people and the State Governments, if they do not take their memoranda into consideration, then they will invite their own danger. Thank you.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : Sir, the hon. lady Member has only repeated most of the criticism that was earlier made. Therefore, I will not reapeat my reply. I will only mention one fact that when the control on the movement of rice was removed, the Chief Minister of West Bengal had also very strongly protested at that time.

He had said hat all this rice would go to hoarder's stocks and prices would go very high. He had created an apprehension in the minds a least of the people of West Bengal that some calamity wac going to come. But nothing happened. All over the country controls on movement were removed West Bengal insisted that at least for the Calcutta regions—Asansol—Durga-pur—Calcutta complex—they should he allowed to retain statutory control. We a-'-et'eH to their request and they maintained it. But now what is happening there in everybody's knowledge. The lady Member also must be knowing it. The Wesi Bengal Government has relaxed all those controls on movement and rice is coming freely into Calcutta. The rice-growers of West Bengal are happy now. The consumers in the Calcutta region are happy now. I can, therefore, assure the honourable lady Member that the same thing will happen in respect of sugar-cane also. All their apprehensions are misplaced. Then she said while our public distribution is being dismantled. ..

SHRI KALYAN ROY : Sugar has already disappeared from Calcutta.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : There is no restriction now. L«t die West Bengal Government come and purchase sugar available in the factories at ex-factory price of Rs- 215. After paying excise duty, costs, etc. it can still be made available to the people at Rs 975 in Calcutta. There is no law which prevents the West Bengal Government from doing it. If they insist on maintaining their public distribution system, let them buy in the open market freely available in all factories Let them take it to West Bengal and distribute it. But there can be no special treatment for the people of one State. The Lady Member keeps on saying West Bengal, Left-Front Government, and all that. Now, the people of West Bengal do not constitute even 10 per cent of the people of this country who have hailed this decontrol of sugar,

PROF. SOURENDRA BHATTA-CHARJEE : Sir, I have listened to with rapt attention to die very bold statement, very bold policy, statements, covering various gamuts of public distribution policy made by the honourable Minister of State for Agriculture By implication he has attacked the policy of subsidised price, that is, public distribution of essential commodities in certain parts of the country, or, in almost all parts of the country. He has expressed his deep concern for the cost of production of the mill -owners. He has made a spirited defence against the levy, to to sa>. Again

e ha? maintained that this levy sugar was b'ing distributed to the rich people to the detriment of the poor people, as if all those living in statutory rationing areas or in raadified rationing areas are rich people. About my State he has already said that the people of my State constitute only 10 per cent of the people of the entire cjuntry and therefore, West Bengal should not be taken into account. He has said 90 per cent of the people of this country have hailed sugar decontrol. We do not know wherefrom he has got this idea. It was introduced iust on the 16th of August And by this time the people all over the country, barring the people of West Bengal, have welcomed sugar decontrol, when even the controlled sugar stocks have not been cleared.

How has he come to this conclusion ? Is it not a very hasty conclusion on his part ? In undermining the Government of West Bengal the Minister referred to the withdrawal of restrictions on movement of foodgrains there. I can tell the House that in West Bengal, the West Bengal Government maintain the public distribution system through their own mechanism in the State. So far as movement of rice to Calcutta is concerned, it has been continuing for a number of years. That is not a new phenomenon. Rice is being distributed both in the statutory rationing areas and in modified rationing areas. The present Government of West Bengal has reduced the disparity between the statutory rationing area and the modified rationing area to a very great extent. That fact should also have been taken into account by the Union Minister when he was out to undermine the present policy of the West Bengal Government on the basis of what he knows from his experience of the situation there on the previous occasion. This is one part of it.

The other part is that the hon Minister has not been able to establish that the decontrol policy was essential for ensuring remunerative price to the sugarcane growers. The Minister shed tears or expressed his indignation when he said that the mills were forced to sell their sugar below the level of cost of [illegible]. [illegible] he compute the cost of production for sugarcane growers ? Nowhere in the course of his speech has he raised this point. What is the cost of production for sugarcane grower ? He did not say that that should be the basis for fixing the price of sugar. Why should he defend the [illegible] of mill-owners ? Is it a very equitable basis ? He did not raise this issue at all.

So far as the price is concerned he has boldly maintained that sugar will be available in Calcutta at Rs. 2.80. I can inform him that sugar is not selling at this price an where in Calcutta in the open market. Sugar is selling in Calcutta in the open market at Rs. 3.40 Kg. It is a fact that Sugar quota for the period upto August, 3 r wa re-eived. I completely agree with Mr. Shahi on this issue. Therefore, the West Bengal Government decided that they should sell sugar upto 31st August through the public distribut! n system. .Secondly, they have repeatedly appealed to the Central Government for increasing their sugar quota particularly in view of the huge stocks that have accumulated. This is supposed to be the basis of the sugar policy fomulated by a committee under the Presidentship of the Defence Minister, Shri fagjivan Ram. Now, this repeated request of the West Bengal Government for increasing their sugar quota from 24,000 tonnes to 32,000 tonnes was turned down by the Union Government. They also appealed that they should be allowed to sell additional anjount so that they could continue distribution of sugar through the public distribution system. That request has also b^n turned down. The sum total of your sugar policy is that the subsidy for export of sugar will continue. The s'uga mills have been freed from their obligat on to make levy sugar available which was 6- per cent of th-' total produce. Now they will offer this quantity in the frie market an I sell thei" entire production at a price of their manipulation and choice. In many parts of the country sugar is either scarce or is selling at high prices.

It has been said that mariy things are not clear. But, Sir. in his mind he is very clea about c-rtain things. Before oractically on the 10th this declaration was made, the mill owners must have got the hint of it because the recommendations of the Committee that was aopointed were made public. So, these manufacturers,, and these traders, who are very adept in the art of mani-pul ation, speculation, blackmarketing, hoa'ding, etc. will do all these things and I thin that he *M* isterwill assure us that if he pr-ce ri*e, he will act. Even in odays discussion, Sir, it was clear that his idea of a reasonable price varies from Rs. Q.80 to Rs. 3.00 ;nd he 1, s -v n declared that if it goes beyond Rs. .0-), in that case, control will be reinvjosed and he pr"sen p licy will be r "ised. But what happened to the largf amounts that will have been accumulated by the manufacturers during the oeriod in between ?... *(Time bell rings)* .Crores of rupees will have been collected and it is our experience that in the past thf manufa tu""r> *'>d

[Prof. Sourendra Bhattacharjee]

the traders, who have been given various concisions, were allow <d to acci n ul. te crores c f rupees and in *lieu* thereof, clan* destinely help was extended to (he ruling parts. We aie not interested to kn<w wh' thei thepre\iousG< vemmcin pursu< d this policy. But we are interested to know whetl er this Government is following the same policy or to what exten t changes have occured. We are interested in the protection of the interests of the con-sumers and the interest of the erne growers and, at the same time, the interests of the worker? in the factories, It is seen now that the cane growers are not going to be benefited additionally by this iri any way. The consumers will be hard hit and the workers also are not going to be benefited. Hence this policy is designed to benefit the mill owners only and the Government is not able to say that it is not so. We would appeal to the Government to look at it from the point of view of the consumers and consumers all over the country and in the interes t f the consumers, this policy, should be changed.

SHRI BHANU PRATAP SINGH t Sir, I would like to just n odifv my reply given earlier to the extent that I siid that ten per cent of the people of the countrv might perhaps not like thii and I would now like to clarify that I have no doubt that the rural people in *West* Bengal will also hail this decontrol. This has happened earlier nd this will happen again. They are sorry only because their scheme did not work. They say that they are allrwing the free flow of rice into the Calcutta region. Why ? If y°u impose statutory rationing, that imrli's thr t not a single grain should be allowed to enter Calcutta. Is it not hypocrisy that on the one hand you say that you are maintaining statn-torv control in an area and, on the other, you close your eyes and allow all the fooderains to enter there ?

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE : But you refused to give more sugar to West Bengal.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : It is true that West Bengal had requested for more levy sugar which we declined and for very good reasons also, the reason being that we cannot adopt two standards. It was decided that all over the country levy sugar would be allowed at the rate of 425 gms. per capita per month and on this basis the West Bengal Government was allowed this quota which was due to. it on the basis of its population. They came out with the argument that if we want to extend this facility to the rural people also, then we should give them additional quota. Now, all the other States were managing within their cwn quota for the rural people also, *iut* they wanted a special enhancement : nd it was not possible for us to accept that ar.d it was not possible for us to accept two stan-dradsfor tie different Statesic the ccuntry.

I have no doubt that the villagers in West Bengal would be happy to get sugar at Rs. a.70 or Rs. 2.75 per kg. The consumers in Delhi and in all the citils also are very high salaried pecple, moneyed people. All the high salaried people are also getting levy sugar which was procured frcm the States at lets th.n the cost of prcducticn. Why wss that done? Why should a perscn getting Rs. 4000/- a month be entitled to get any commodity at less than the cost price ? Why is that done? This is distcrting the economy altogether. And Sir...-

BP

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): In a controlled econcmy it is inevitable. What are you talking?

SHRI BHANU PRATAP SINGH : We do not have a fully controlled economy.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We have taken a lot of time on this. There are still.. *(Interruptions)* I do not want to hold up any discussion. If the House is not prepared to discuss anything else... *(Interruptions)* There should be some time-limit. *(Interruptions).*

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Decontrol is the result of money having been passed from the millcwners to some pockets in the ruling party.^

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Uttar Pradesh) : Including Bhu-pesh Gupta.

SHRI SUJAN SINGH (Haryana) : Both as a Member of Parliament and a farmer, I want to shower my praise on this Janta Government, Janata party and also the hon. Minister, for taking this decision.... *(Interruptions)* If we analyse the situation prevailing before decontrol, we would definitely come to the conclusion that it is a rorre cl decision. What was the condition before the decontrol? It was more production and less take-off. Now what will happen ? More sugar will be consumed in the country, which is in the inteiest of the millcwners, in the interests of farmers and in the interests of the country as a whole. Now, we are expecting record production during this year, 1978-79 about 65 lakh tonnes. If decontrol had not been done, there would have been a huge crisis and the Government weuld not have been able to take care of it.

We would have again criticised the Go-' vernment iirthc month of Ccie LOT. Big stocks of sugar would have been accumulated and there would have been payments ofheavyinterest and factories we ukl thus be losing the'r own piofits. Sugar mills were becoming more and more sick day by day which again is rot in the interests of the farmers or in naticna] interests. Farmers were burning their cane; cane was nor taken up by factories as it was becoming unprofitable fcr them to purchase the cane. Those people who were having ration shops in the rural areas were also making black money by not supplying sugar to the rural people. Members of Parliament even during tie last session were also criticising the Government and they were persuading the Govenemer.t in this House that there should be no dual control.

But, now when this Decontrol has been done the opposition for the sake of opposition continues. My friends in the opposition should not criticise the Government on this issue. This was the occasion when they should have joined us in congratulating the Government. Now, what will happen after decontrol. More sugarcane will be consumed by the factories for more sugar production with the result that the farmers will be saved from burning their crops. They will get more encouragement for growing sugarcane. The mills will also be saved from being ruined. The hon. Minister has rightly said that if the mills are ruined, the farmers will also be ruined. The mills are tl e hands which lay the golden eggs for the farmers provided they are not allowed to become fat. If the hens die for short of food farmers will also have to suffer. Therefore, this decision is in the interest of the farmers, the mill-owners who will also be able to earn reasonable profits, the Government and the nation alike. This decision is not in the interest of any one community or class. This is the decision which' we should all welcome as it benefits reasonably all classes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Let the replv be given at the end.
MR. Naidn.

SHRI N.P. CHENGALRAYA NAIDU (Andhra Pradesh) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I will thank the Government for decontrolling sugar. But I m not happy with the Government for fixing the price of sugar atRs. 2.75 per kilo and the price of sugarcane at Rs. 10 per quintal. Actually, the cost of cultivation of sugarcane comes to Rs. 16 or Rs. 17 per quintal.

SURI KAJT JVAlIi PAI: 11 is is anti-kism j'c!k\.

SIR] lN.r.CHl>CAlFAY/ 1^11 l Wha; is the ute r 1 fix re; the fiic< ails, io? Fn\ki.;]y. ill Cc\<JII. 'i! decided to sekasc the Luck c! k.lcu v.U'.c ever it was existing.

Eut the agriculturist; in tt< cciiuy are treated as herded Iatcti u cki tl \i Gcveirn.dH at well as ur.de i tl t tici Coveirnur.i. We are th< 1 <i <k d laht 11. If we product jncre, tley fx s< v < pier. II we want to st.'J, they Ljii £ :<n I ctft-rrl. This is the bended labour policy. When we want to purchase fertilise! s, they increase the price ft cm F,,. 4-/ to Rs. ico/-. Notcdy can ask thipi. They are the masters and wr aic tl< 1 11 -ded labourers. So, they inert a EC the price. When we need electricity, the charges are increased. When we want tractors, we are charged fcr a 40 F.P tractor and we are given a 25 F)P tractcr. A tractor by Hindustan Traders v:s labelled as 25 HP tractcr. When it was tested, it was found to be a i€ I P tractcr. They deceive the faitrWis. They increase the prices not enly tractors but also of dicsel and fertilisers. AH these prices have increased. I fin not blaming the Janata Gcvcirmert. Even Mrs. Indira Gandhi's Goveirmcrt was doing the same thing.

AN HONOURABLE MEMEIR : What abc tit Morarji Desai's Government ?

SHRI N.P.CHENGALRAYAKAlIU< I say that both this Government grid the previous Government are the same. They are the masters ard we ere the bonded labcuiers. This is the pesitkn. We have got four classes of people. Cre class consists of agriculturist; who \ en the land, labourers who work as agricultural labourers and the labourers \ w'ork in the factories. The secend class consists of middle-class traders. I am not thinking of big traders. They are black marketeers. I do not want to brii c them into this thing. I talk only ah<vt the middle-class traders. The third cateogory consists of educated people like doctors and engineers who work in offices and other places. The fourth caret cry cons'sts of those who do not work at all. They do not do anything. They are parasites on the agriculturist'. They are parasites on the country. They eat us. Still we have to produce and feed these parasites. We do not knew what to do. We thought that this Government would help us.

SHRI N.K.P. SALVE : Who are the parasites ?

SHRI N.P. CHENGALRAYA NAILU: Most of the politicians are parasites.

[Shri N.P. Chengalraya Naidu]

Why do you want details? There are *otluc* parasites also like the big industrialists. Whv do you want all the details? Sir, this is the position. Irt the recent elections, the agriculturists stood behind the Janta Party. They voted the Janata Party to power thinking that they would help these agriculturists. Now, what is the return that they are getting? We are not able to get anything. That is why, Sir, I ask the Minister: Is it not a fact that to produce a quintal of sugarcane, it costs Rs. 16 to Rs. 17? Take the cloth, Sir? It was available for 25 paise or 50 pa'se per metre. Now they are paying Rs. 4 per metre. But there is no coraplant When they come to sugar, the complaint is there. Can't you increase the price ? How much do they consume ? They consume only a little sugar to add to their coffee or tea. For that, they do not need so rr.uch sugar. Why can't they increase the minimum price to Rs. 4/-? I am for one thing, Sir. Let the Government take 25 per cent of the sugar from the sugar factories at the controlled rate. Let it be distributed to the poorer sections of people who work in the factories or the fields and such people whose income is less than Rs. 200 or Rs. 300. We are not objecting to that Let it be distributed like that. For that, even if I an required to sell one tonne or two tonnes at the controlled price, at a price less than the cost price, let it be. L^t th?m distribute it to the poorer sections of the society . We do not object to that- ftut what is th- G">vrmn»nt doing? They are in the hands of the parasites . Whenever there is a hue and cry from them they please those parasites but not the agriculturists who produce the foodgrains or the sugarcane. Sir I want the Government to release us from that bonded labour at least from now on. That is my request to the Government.

SHRI AMAR PROSAD CHAKRA-BORTY (West Bengal) : Mr Deputy Chairman Sir

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shri Raghunatha Reddy. *(Interruptions)*

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI LAL K. ADVANI) : Everybody wants to speak But the House has to be conducted, Sir.

MR DEPUTY CHAIRMAN : I said only one person from each Party. A large number of people wanted to ipeak. Mr Sujan Singh insisted on speaking. Mr Naidu was very much insisting to speak. And no one wanted to close the discussion. I had no other alternative but to ask them to speak. I have . ..

SHRI KALYAN ROY : You are very fair Sir.

MRf DEPUTY CHAIRMAN :... plenty of slips here:

SHRI K.V. RAGHUNATHA REDDY: (Andhra Pradesh) : Mr Deputy Chairman, Sir, having observed the replies of the hon Minister. I was rather not only amazed but frightened about the way in which the economic problems of the country are being dealt with. On a high authority from Bengal I learn that the entire sugar in Bengal has disappeared and I am not given to listening to rumours. I am speaking from die information that has been given to me from a very high authority, and in fact the government ot West Bengal if I may say so. And I don't think that the Government of West Bengal can be irresponsible. The Government of India cannot say that government of West Bengal does not have the information at its disposal.

[The Vice-Chairman (Shri Syed Nizam-Ud-Din) in the Chair]

Apart from this Sir previously whenever there was a sugar decontrol there used to be a strong suspicion not an innocent affair but quite a sordid story-behind every sugar decontrol. I am afraid the same thing appears to continue even now

SHRI V. V. SWAMINATHAN (Tamil Nadu) : It used to happen at election times.

SHRI K.V. RAGHUNATHA REDDY; Sir this is a very sad state of affairs. Sugar decontrol is not such an innocent affair as it is sought to be depicted. Even in Delhi there is the danger of sugar prices going up. Sugar has already gone into hiding and black market would start now. This is the situation which I want the Government to seriously realise. Whenever sugar decontrol was undertaken I can tell you with a certain amount of knowledge of the subject the Ministers were led to believe that it would reduce the prices. This is the pathological phenomenon which afflicts almost every Minister in the Government This is a very sad state of affairs. Every Minister who deals with the subject seems to believe that as soon as there is decontrol there would be plenty of sugar available. Unfortunately the situation is different. Same is the case in relation to cotton. Same is the case with regard to jute. Same is the case with regard to cement. Same is the case with regard to edible oils. This is the situation into which the Government is leading itself. There are very responsible Ministers here. Mr Vajapayee Mr Advani and other friends

are here. I would like them to realise that they have reached a stage where the transfer of resources from rural sector is fast taking place into the industrial sector and the industrial sector is not in a position to invest it in further production. That is why all this kind of economic gerrymandering is taking place on the economic front. This represents the most dangerous situation apart from the devaluation of the rupee which is also linked with the international economic market. This is the situation which I want the hon. Minister to understand and also the distinguished Cabinet colleagues of the hon. Minister to understand before the economic situation goes out of hand. People lose faith, I do not mind if they lose faith in the Government. If the people lose faith m the political and economic institutions that this country had nurtured so far and if people lose faith in the democratic institutions and the democratic way of functioning of our polity, then there is the real danger which any Government of this country will have to face. It does not matter whether one Government goes and anodier Government comes. The only answer for this is that all the saner elements in Indian society must join hands for the purpose of defending the interests of the people and saving this country from chaos and disorder.

In the meantime, Sir, I am afraid the peasant is not going to get even one naya paisa benefit out of the rise in prices. Well the same is the situation in U.P. The same is the situation in Andhra Pradesh. And do you know that the peasantry has risen in revolt in Tamil Nadu? For the first time in the history of Tamil Nadu the peasantry has risen in revolt and all tributes to them at least to those who have come out into the streets to fight for their rights.

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh) : And same is me "situation in U.P. also.

SHRI K. V. RAGHUNATHA REDDY : In such a situation Sir, I do not want the Government and its leaders to mislead themselves into believing that decontrol of sugar is going to help them. I wish them well. I do not want that the Government must fall on this ground. I do not want that the people should lose faith in the political institutions that the country had built up step by step. Whatever step the Government might take I am afraid, this is the ultimate effect on the psychology of the people. I do not want to enter into a debate. If it is a question of debate on the economics of su^ax T am afraH. I know much more than what the Govrnment knows. TF it is a qri ion of discussion of the economic problems, devaluation of the rupee or ef the pound or a debate on the industrial sector. I can easily point out the shortcoming of the Government on these questions. But I do not want to enter into a debate on this matter. I want them to understand realistically and wiuh a sense of objectivity what is happening and how the people also react. It is not merely a question of what the Government believes. You should also understand how the people react. I want them to realise diis and I do not want to enter into a debate. I have no doubt in my mind that this is a very disastrous policy of decontrol and I am opposed to it became all decontrols have been disastrous so far. Thank you.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : I can only say that old suspicions persist. It has been said that in the past when decontrol was made, it produced disastrous results. It is true and *1* would also, in those circumstances, have not advised decontrol. But the circumMan-ces are entirely different today. I will read some figures. In 1969^70, production of sugar was 42.6 lakh tonnes. In I970-7[1]. it was 37.4 lakh tonnes and in 1071-72, it was 31.3 lakh tonnes. There was a declining trend in the production of sugar and at that time I do nit know under what advice the then Government decontrolled the sugar. But today, the conditions are entirely difli u nt. We have produced much more than last year which was itself a record production and we have produced nearly the same this year and It may be the same next year also. Therefore, the circumstances are not comparable at all.

Now, the point has been raised about the consumers. Do the consumers live only in cities ? I have no doubt that more people live in villages : even in absolute numbers more people will b< nf fit by decontrol thn to pay a little higher price in the cities. I can also say that under decontrol also, the price of lrvy sugar would have to be revised and it would have to be raised to Rs. 2.50 per Kg. Now if we have to revise it to Rs. a.50 and leave all the black marketing : n ' ev rything that was going en, if it not much better that we are able tc svpply to the people of this country sugai at Rs. 2.75. *(Interruptions).* As far as the West Bengal Government is conce nrd, sugar will reach, I have no doubt, ?nd it was decontrolled only...

SHRI KALP NATH RAI : साउथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू में 3 रु० किला चीनी नहीं मिल रही है, आप गांवं में चीनी भे-ं हे हैं। 2 रु० 75

[श्री कल्प नाथ राय]

पैसे में? यह सरकार ं जीपतियों के हाथ बिक रही है ।

<5HTH BH\NU PRATAP oiiNun . As "L the price is concerned, if the dii^I pricing system had continued, we w"u d be left with 32 lakh tonnes of sugar hv the end of this sugar season. Ihe co^t ^ sugar is nearly Rs. 720 crore, I? that afcoUnt of money remained oocLd, then I have no *ubt that mo t of the factories would not be able to surt the crushing season. Nov, with decontrol, we hope that more sugar w 11

[eft in thf godovvn. of the sugar factories £'i would have been if the control had continued, then I have no doubt hat S s "uUr industry would have coUap-2d As far as. pricing is concerned I am in great sympathy with the hon. Member here and I can assure him that if the pricing concerns some commodity fke wheat or rice or anything which i, no? perishable and of which there is demand in the country and also abroad I would certainly like to give a better Price to the producers. But what about The sugar cane ? It cannot be preserved It cannot be exported. It is in the be. interests of the sugar cane growers that ^hey reduce the area under sugar cane If they had taken my advice which I have repeatedly been giving during the last A months, then I am sure per-h,p3the n -eJ would not arise to lower the price of sugar cane.

4 P.M.

But mv advice has not been heeded to Thev keep on complaining that ,h'e price of sugarcane is very low. It it is very low, why'is the area <nd production 'goin- up year after year? lean Si you lh«t there' are alternative crop-*XJ* patterns wnich can give hither Si t3 fee growers. Those who , are ve Wisher *J* farmers, should advise them to switch over to other cropping SSna. If they do- *I* have i, o ihat the price of sugarcane will again.go ,in Rut in the circumstances ol today - XenWvcnne * sugar cannot be stored for long or-it cannot be consumed, it would be very unwise to raise the price of sugarcane and then to encourage them to grow more and again invite a lot of trouble for ourselves, for sugai factories and all over. I would also like to repeat that there |r no confrontation between the industry and the cane growers II there is confrontation, it is between the cane growers and industries and the social parasites to which the hen. Member has referred. I would not go into detail as to who are the social paifisiu:. K;t I have no doubt in my mind that it is these social parasites who have b«n manipulating in a manner that th* »gri» culturists of this country have been maltreated in the past and I asswe \r.11 that as far as I am concerned, as far as this Government is concerned, the ir.Kmts of the agriculturists will alvays be uppermost.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa) : Sir. actually 1 $m r.t 1 gciig into a bitter controversy ovci item like sug^r as many other MM. have dealt with it. The enlyrtim il at I want to make is that after a 1< rg time a legacy of the past Government has been dene away with by decontrolling sugar. I very loudly stend for deccntrol and I place en record my support for the same.

Sir, so far a group of "Blue Bleed" p< cple were consuming this fair price rcmioljed sugar and the rest of the entire mullmele of the country were suffering frcm the high price that was going on all these years, and in the periphery people were not getting sugar even by paying Rs. 5 per kg. I only request the Government that the price of sugar may be fixe d and at the same time interest of the faimers must also be looked into. This year so many farmers were unable to cut sugarcane because the cost of cutting sugarcane was higher then the cost of sugarcane itself. Therefore, the price of sugarcane must be protected. So much so that all these farmers may be given subsidy or some advance assistance for the cutting and selling processes. Due to heavy flood this year in TJ. P. and Bihar we expect a bumper crop of sugarcane. Letnot the farmer suffer as before. Their interest may be protected by raising the cost of sugarcane per tonnage. Fixing of suage price is not alarming for anybody because so far more than go per cent of the sugar consumers were paying Rs. 5 per kg. They had to pay still higher rates for items based on sugar, like chocolates, lemon juice,etc. Some bogus industries which are processing Sugar into chocolates, lemon juice, etc. are actually selling one kg. sugar at Rs. 20 or more. The Government should see that a large quantity of sugar diverted into those bogus industries is minimised. Sugar must be consumed as sugar. In case there is any fallacy anywhere, the Government should check it. If necessary, the Government should start even fair price shops to sell sugar at fixed price all over the country. I again want to go on record that whatever may be the opposition in this House or elsewhere wc

shall not go back a step. Decontrol is a must. After all, we have done away with the dual policy which the last Government was. carrying on.

A group of "Blue Blood" such cannot flourish by taking advantage of any such lacuna in the Government machinery to carry on black market on sugar in the periphery and hobnobbing with the sugar magnates in the Centre.

The persons who have been shouting here their agencies in the periphery were helping black marketing and taking sugar every day on the pretext of the brother's or sister's marriage and so on. And their leaders were hobnobbing widi the sugar magnates. We have really done a good thing in that we have fulfilled the mandate for which the people voted us. My only emphasis is that the interests of the sugarcane growers must be kept in mind.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : Sir, I have noted all the suggestions of the hon. Member and will look into these,

MOTION FOR ELECTION TO THE TEA BOARD

The question was put and the motion was adopted.

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"चाय नियम, 1954 के नियम 4 के अधिनियम (i) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 (1952 का 29) की धारा 4 की उप धारा (3) (च) के अनुसार यह सभा उस रीति से, जैसे सभापति निदेश दे, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को चाय बोर्ड का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे ।"

REFERENCE TO THE REPORTED DEMAND BY INDIA TO REVOKE FARAKKA AGREEMENT

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं सरकार का और सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । बंगला देश के कुछ समाचार-पत्रों में छपा है कि फरक्का एग्रीमेंट संभवत: रद्द किया जाएगा । मेरे पास समाचार-पत्रों की जानकारी है । मैं संबंधित उद्धरणों को यहां पर पढ़ कर सुनाना चाहूंगा । वहां का एक 'देश बंगला' नामक समाचार-पत्र है जिसमें 11-8-78 को डिप्लोमेटिक सोर्स को कोट करते हुए यह कहा गया है कि—

"The question that the agreement might ultimately have to be terminated arose after the fifth meeting of the Joint River Commission in New Delhi from July 5 to 11 at which Bangla Desh proposed that there was no alternative to seeking the cooperation of Nepal so that dams could be constructed in her territory to augment the dry season flow of the Ganges. India opposed die proposal on the ground diat the problem should be solved bilaterally, and that it was neidier desirable nor feasible to bring a third country into this question."

इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बात भी कही है । उन्होंने यह मांग भी की है कि बंगलादेश और भारत के साथ-साथ इस वार्ता में नेपाल को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा है कि इसकी आवश्यकता इसलिए और भी बढ़ गई है कि भारत शायद अगली बैठक में फरक्का एग्रीमेंट को रद्द करने की मांग करेगा । इस संबंध में उन्होंने पी०टी०आई० समाचार समिति का हवाला दिया है । इसलिए मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंगलादेश की सरकार इस मामले में घपला डाल कर हम पर दोष डालना चाहती है कि फरक्का एग्रीमेंट को गोया कि हम तोड़ रहे हैं । इस प्रकार का प्रचार करके वह हम पर दबाव डालना चाहती है । इस समाचार में पी०टी० आई० का हवाला दे कर यह कहा गया है कि :

"Analysing the agreement, the PTI story which quoted knowledgeable circles, Baid that India might reconsider the